आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

एस. एस. सारोन राजीव नारायण रैना और लिसा गिल, से पहले जे. जे. (एफबी)

दीपक अग्रवाल और एक अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. No.4371

31 अगस्त, 2017

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894- धारा **4, 5-ए और 6-भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013-**धारा **। 24 और 114-सामान्य खंड अधिनियम, 1897-**धारा **6-1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना-यह नहीं कहा जा सकता है कि 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) द्वारा विचार किए गए अनुसार अधिग्रहण की कार्यवाही 'शुरू' की गई है-अधिग्रहण के लिए कार्यवाही को** विवेक के **अनुप्रयोग के बाद ही शुरू किया जा सकता है यानी 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा का चरण-यदि अधिग्रहण की कार्यवाही 1894 अधिनियम के तहत 'शुरू' की गई थी, लेकिन खंड 11 के तहत कोई** फैसला **नहीं दिया गया था, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित 2013 अधिनियम के प्रावधान लागू होने हैं-आधिकारिक राजपत्र में 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत प्रकाशित अधिसूचना लेकिन 2013 अधिनियम के प्रारंभ के बाद समाचार पत्र में अर्थात 01.01.2014-इस तरह के प्रकाशन और सार्वजनिक सूचना देने की अंतिम तिथि के रूप में टिकाऊ नहीं है।** सुनवाई 01.01.2014 के बाद धारा 5 ए के तहत आपतियों और 1984 अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन को अनुमति नही है। धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ पुराने 1894 अधिनियमके तहत कार्यवाही शुरू नही की जा सकती है।

माना गया कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के अनुसार 'शुरू' की गई थी क्योंकि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना नए 2013 अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले जारी की गई थी।नए 2013

अधिनियम की खंड 24 पुराने 1894 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित है जिसे कुछ मामलों में समाप्त माना जाता है।खंड 24 का उक्त शीर्षक कुछ मामलों में पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही के समापन का प्रावधान करने के लिए है।इसकी उप-खंड (1) (ए) में उल्लेख किया गया है कि नए 2013 अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, पुराने 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के किसी भी मामले में, जहां पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत कोई निर्णय नहीं दिया गया था, नए 2013 अधिनियम के सभी प्रावधानो से सम्बन्धित मुआवजे का निर्धारण लागू होना है।

481

और अन्य (S.S.Saron, J.)

इसलिए, नए 2013 अधिनियम की खंड 24 की उप-खंड (1) के खंड (ए) के प्रावधानों को लागू करने के लिए पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई होगी।यह तभी होगा जब पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत कोई निर्णय नहीं दिया गया था , तो मुआवजे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए नए 2013 अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।मुआवजे के भुगतान का निर्धारण करने के उद्देश्य से पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करना नए 2013 अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए एक अनिवार्य शर्त है , 01-01-2014 से नया 2013 अधिनियम लागू होने से पहले 28-10-2013 को पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत केवल अधिसूचना जारी करने के साथ , यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी और इसके परिणामस्वरूप निकाय पारित नहीं किया गया था, नए 2013 अधिनियम के संदर्भ में मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधान लागू होने थे।वास्तव में, यह पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा है जिसमें प्रस्तावित अधिग्रहण को अंतिम रूप दिए जाने की दृढ़ता का एक तत्व है जिसमें यह कहा जा सकता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।यह कहा गया था कि खंड 4 के तहत जो केवल एक प्रस्ताव था, वह पुराने 1894 अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए एक निश्चित कार्यवाही का विषय बन जाता है। नया 2013 अधिनियम लागू होने के बाद 27-10-2014 को खंड 6 के तहत जारी की गई घोषणा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नया 2013 अधिनियम लागू होने से पहले पुराने 1894 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

(पैरा 93)

आगे कहा गया है कि नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे और पुराने 1894 अधिनियम के तहत की जा रही अधिग्रहण कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा।नए 2013 अधिनियम की खंड 114 के प्रावधानों में यह भी परिकल्पना की गई है कि पुराने 1894 अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था।इसका मतलब यह होगा कि इसे 01.01.2014 से नए 2013 अधिनियम के लागू होने के साथ ही इसे निरस्त कर दिया गया था।नए 2013 अधिनियम की खंड 114 की उप-खंड (2) को निरस्तीकरण के प्रभाव के संबंध में 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 का खंड (सी), जो वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक है, यह परिकल्पना करता है कि जहां कोई केंद्रीय अधिनियम अब तक किए गए या इसके बाद किए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है , जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है , निरसन इस तरह से निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के तहत अर्जित , उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार , विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।1897 जी. सी. की खंड 6 की प्रयोज्यता

अधिनियम प्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि नया 2013 अधिनियम लागू होने से पहले केवल खंड 4 अधिसूचना जारी करने के साथ भूमि अधिग्रहण कार्यवाही , पुराने 1894 अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के बराबर नहीं होगी।

(पैरा 94)

(2) पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत 01-01-2014 के नियत दिन से पहले जारी की गई अधिसूचना खंड 6 या 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 के आधार पर लागू **नहीं रहेगी।**

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है और ऊपर विचार किया जा चुका है, नियत दिन यानि 01.01.2014 से पहले पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 को देखते हुए प्रभावी नहीं रहेगी। इसका कारण यह है कि 1897 के अधिनियम की खंड 6 को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए और इसे नए 2013 के अधिनियम की खंड 24 (1) के संदर्भ में माना जाना चाहिए। पुराने 1894 अधिनियम के जिन प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है , वे उन मामलों में लागू रहेंगे जब पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही 01-01-2014 के नामांकित दिन से पहले शुरू की गई

थी और अन्यथा नहीं।इसलिए, ऐसे मामले में जहां पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत एक घोषणा प्रकाशित की जाती है और 01-01-2014 से पहले अधिसूचित की जाती है , पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही को नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया कहा जा सकता है और ऐसे मामले में जहां पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित नए 2013 अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे। मुआवजे का भुगतान इस प्रावधान के अधीन है कि जहां निर्णय किया गया था और अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया था , तो 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

(पैरा 98)

आगे माना गया, इसलिए, नियत दिन से पहले पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी की गई अधिसूचना 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 के साथ पठित खंड 6 को देखते हुए प्रभावी नहीं रहेगी क्योंकि एक पूरी तरह से नया लाभकारी कानून प्रभावी हो गया है जिसे उन लोगों के पक्ष में पढ़ा जाना चाहिए जिनके लाभ के लिए इसका इरादा है।हालाँकि , यह उस मामले को अपने दायरे में नहीं लेगा जिसमें पुराने 1894 के अधिनियम, के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी।

483

और अन्य (S.S.Saron, J.)

जैसा कि ठीक से समझा गया है , नियत दिन से पहले, कौन सी कार्यवाही, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है , अधिग्रहण के उद्देश्य से पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत एक घोषणा के प्रकाशन के साथ शुरू होगी।

(पैरा 105)

(3) सरकारी राजपत्र में पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत प्रकाशित अधिसूचना, लेकिन बाद में समाचार पत्रों में प्रकाशित, यानी नए 2013 अधिनियम के शुरू होने के बाद

01.01.2014 को **कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है-अधिसूचना की आगे की अंतिम तिथि पर प्रकाशन की प्रक्रिया को पूरा कहा जा सकता है, उस पर विचार किया जाना** जा सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत आधिकारिक राजपत्र में , लेकिन बाद में नए 2013 अधिनियम के प्रारंभ के बाद समाचार पत्र में 01.01.2014 को प्रकाशित अधिसूचना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं होगी क्योंकि इस तरह के प्रकाशन की अंतिम तिथियां और ऐसी सार्वजनिक सूचना देने को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में जाना है। अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन पर ही यह कहा जा सकता है कि प्रभावित पक्षों को नोटिस दिया गया था ताकि वे आपत्तियां दर्ज कर सकें।

(पैरा 112 (जी))

(4) खंड 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन इसके निरसन के बाद और नए 2013 अधिनियम के शुरू होने के बाद 01.01.2014 से अनुमत नहीं है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि खंड 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन इसके निरसन के बाद और नए 2013 अधिनियम के प्रारंभ के बाद 01.01.2014 से अनुज्ञेय नहीं होगा क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी , यदि इसकी खंड 6 के तहत घोषणा जारी नहीं की गई थी और यह केवल तभी कहा जा सकता है जब घोषणा जारी की जाती है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को 'शुरू' किया गया था।दूसरे शब्दों में , यदि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के संदर्भ में घोषणा 01-01-2014 से पहले अधिसूचित नहीं किया जाता है, तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई नहीं कही जा सकती है और इसलिए , नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के आधार पर समाप्त हो जाएगी।

(पैरा 112 (एच))

(5) सामान्य खंड अधिनियम, 1897-खंड 6-निरसन का प्रभाव-निरसन का उद्देश्य खंड 6 के तहत प्रदान किए गए कुछ उद्देश्यों को छोड़कर, अधिनियम को प्रतिमा पुस्तकों से मिटा देना है।

यह माना गया कि 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 में निरसन के प्रभाव का प्रावधान है। इसमें अधिनियम का प्रावधान किया गया है जिस में 1897 जी. सी. अधिनियम या 1897 जी. सी. अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियम अब तक किए गए या इसके बाद किए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है , जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो। निरसन खंड (क) से खंड (ङ) में उल्लिखित परिस्थितियों को प्रभावित नहीं करेगा।खंड (बी) में प्रावधान है कि निरसन इस तरह से निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम या उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी कार्य के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।एक अधिनियम का निरसन आम तौर पर कानून को समाप्त करने के लिए होता है जैसे कि निरस्त कानून कभी मौजूद नहीं था।निरस्त करने का उद्देश्य 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के तहत प्रदान किए गए कुछ उद्देश्यों को छोड़कर , अधिनियम को कानून की पुस्तकों से मिटा देना है। विधायिका का इरादा यह एकत्रित करना है कि निरसन का उद्देश्य और उद्देश्य क्या है। इस तरह के इरादे बाद के विधान के स्पष्ट प्रावधानों या उसमें से आने वाले आवश्यक निहितार्थों से पता लगाया जा सकता है।बाद के क़ानून से यह पता लगाया जाना है कि क्या विधायिका का इरादा पहले के अधिनियम को पूरी तरह से या केवल आंशिक रूप से समाप्त करना था।

(पैरा 95)

एम. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता,

नितिन सरीन, अधिवक्ता,

रितेश अग्रवाल, अधिवक्ता,

अंकिता समब्याल, अधिवक्ता और

शक्ति सिंह, अधिवक्ता,

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4371 में याचिकाकर्ताओं के लिए।

शैलेंद्र जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता,

मन्नू चौधरी, अधिवक्ता,

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 6419 में याचिकाकर्ता के लिए।

पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतीक गुप्ता, अधिवक्ता

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. No.8963 में याचिकाकर्ताओं के लिए।

पी. एस. खुराना, अधिवक्ता,

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. No.12758 में याचिकाकर्ताओं के लिए।

अमर विवेक , अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा , 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. नम्बर 4371 में उत्तरदाताओं के लिए संख्या 1,2 और 4 के लिए।

दीपक अग्रवाल और एन्नदर बनाम हरियाणा राज्य

485

और अन्य (S.S.Saron, J.)

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 12758 में उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के लिए

चेतन मितल वरिष्ठ अधिवक्ता उदित गर्ग, अधिवक्ता और

एच. एस. आई. डी. सी. प्रतिवादी नम्बर 3 के लिए अधिवक्ता मायानक अग्रवाल अधिवक्ता।

एस. एस. सारोन, जे.

(1) यह निर्णय और आदेश दीपक इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा 18.08.2015 पर पूर्ण पीठ को दिए गए संदर्भ का निपटारा करेगा।

[दीपक अग्रवाल और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य

2015 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4371] के मामले में तथ्य उक्त रिट याचिका से लिए गए हैं , हालांकि संबंधित याचिकाओं में उपस्थित वकील ने भी प्रस्तुतियाँ दी हैं जिन पर विचार किया जा रहा है और उन पर निर्णय लिया जा रहा है।

(2) याचिकाकर्ताओं-दीपक अग्रवाल और एक अन्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका के माध्यम से हरियाणा सरकार (उद्योग और वाणिज्य विभाग) द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ('पुराना 1894 अधिनियम'-संक्षेप में) की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना और उक्त पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/घोषणा दिनांक 27.10.2014 को रद्द करने की मांग की है।

(3) याचिकाकर्ताओं के पास जिला अंबाला की तहसील साहा के गांव टेपला में 5 एकड़ जमीन थी और उनके पास थी।दोनों याचिकाकर्ता अपनी पत्नियों श्रीमती मधु अग्रवाल और श्रीमती सुनीता अग्रवाल के साथ अधिग्रहित भूमि के 50 प्रतिशत सह-हिस्सेदार हैं, जो 19 कनाल 12 मरला की भूमि के संयुक्त मालिक भी हैं। याचिकाकर्ताओं की संबंधित संपत्तियों का वर्णन याचिका में साईट के सहायक मानचित्र के साथ किया गया है।

(4) हरियाणा सरकार ने इससे पहले 23-12-2005 को पर पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें साहा में विकास केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से गाँव ढकोला, साहा, टेपला और जवाहरगढ़ में स्थि त 278 एकड़ 1 कनाल भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया गया था।(उक्त अधिग्रहण कार्यवाहियों को इसके बाद 'पिछली अधिग्रहण कार्यवाहियों' के रूप में संदर्भित किया जाता है -संक्षेप में)।याचिकाकर्ताओं के अनुसार , पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 23-12-2005 कोई प्रकाशन पुराने 1894 अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार इलाके में नहीं किया गया था। कोई 'मुनादी' (घोषणा) नहीं थी।

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के संबंध में इलाके में कार्यवाही की गई और न ही पु राने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना को किसी सुविधाजनक स्थान पर चिपकाया गया था।

(5) याचिकाकर्ताओं, अर्थात् दीपक अग्रवाल और कल्याण अग्रवाल ने किसी भी मामले में, पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत उप -मंडल अधिकारी -सह-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर

(संक्षेप में 'कलेक्टर') के समक्ष उक्त अधिसूचना दिनांक 23-12-2005 आपत्तियां दायर की। पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत कार्यवाही में , कलेक्टर को यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं में से किसी को भी कोई नोटिस जारी किए बिना आपत्तियों की सुनवाई की एक सुनवाई की तारीख 01.04.2006 निर्धारित की गई है।आपत्तियों की सुनवाई की तारीख कथित और अघोषित तिथि पर, जिससे याचिकाकर्ता अनजान भी थे, वे कलेक्टर के सामने पेश नहीं हो सके और न ही वे अपनी आपत्तियों का समर्थन और पुष्टि करने के लिए कोई सबूत पेश कर सके। हालाँकि, कलेक्टर ने पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत एक रिपोर्ट तैयार की और इसे राज्य सरकार को सौंप दिया। वास्तव में, कलेक्टर को 901 आपत्तियां प्राप्त हुईं और इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियों /विरोधियों को एक ही दिन में सुनना मानवीय रूप से असंभव था।दाखिल की गई रिपोर्ट में भूमि मालिकों को किसी भी व्यक्तिगत और/या व्यक्तिगत नोटिस जारी किए जाने का कोई उल्लेख नहीं था।

(6) हरियाणा सरकार ने 'पिछली अधिग्रहण कार्यवाही ' में याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली भूमि सहित भूमि के संबंध में 29-12-2006 को पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत एक अधिसूचना जारी की। 20.01.2008 को अन्य लोगों के साथ याचिकाकर्ताओं ने एक रिट याचिका दायर की , यानी 2008 का CWP नंबर 1048, इस अदालत में पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत जारी दिनांक 29.12.2006 और खंड 4 दिनांक 23.12.2005 के तहत जारी की गई अधिसूचनाओं पर आरोप लगाते हुए। उक्त याचिका में इस न्यायालय ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किए और याचिकाकर्ताओं को उनकी भूमि से बेदखल करने पर रोक लगा दी।इसके बाद हरियाणा सरकार ने पुराने 1894 अधिनियम की खंड 48 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि का एक बड़ा हिस्सा छोड़ने का फैसला किया , जो विवादित भूमि के समान ही स्थित था।

(7) इस बीच कलेक्टर ने 'पिछली अधिग्रहण कार्यवाही' में 15.11.2006 को विचाराधीन भूमि के संबंध में अपना निर्णय पारित किया। हालाँकि, इस न्यायालय ने 16.12.2010 पर याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा दाय र रिट याचिका , यानी 2008 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1048 को अनुमति दी।अन्य बातों के साथ साथ साथ यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए, अधिग्रहण की कार्यवाही को कानूनी रूप से अस्थिर माना गया। इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.12.2010 को पारित हुआ, पुराने 1894 अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया।

रिट याचिका में केवल याचिकाकर्ताओं के संबंध में रद्द कर दिया।

(8) याचिकाकर्ताओं ने अपनी पत्नियों के साथ 31.03.2011 को 'पिछली अधिग्रहण कार्यवाही' में अधिसूचनाओं को रद्द करने के बाद निदेशक , टाउन एंड कंट्री प्लानिंग , हरियाणा, चंडीगढ़ को आवेदन किया कि वे जमीन के मौजूदा उपयोग को "टेपला गांव, अंबाला कैंट में मध्यम क्षमता के औद्योगिक पिछड़े क्षेत्र में कृषि के अलावा गोदाम के लिए भवन " में विकसित करने के उद्देश्य से भूमि के मौजूदा उपयोग को बदलने की अनुमति के लिए आवेदन करें। ".आवेदन के साथ-साथ रुपये 2,98,000-के ड्राफ्ट सहित विभिन्न दस्तावेज जमा किए गए थे।कार्यकारी अभियंता, हरियाणा, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), अंबाला ने 29.03.2011 को याचिकाकर्ता की भूमि तक पहुँचने वाली सड़क /पथ के निर्माण के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र ' प्रदान किया। निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग , हरियाणा, चंडीगढ़ ने 09.12.2011 को याचिकाकर्ताओं को अन्य बातो के साथ–साथ लिखा कि 'भूमि उपयोग बदलाव' ('CLU'-संक्षेप में) के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि आवेदन किया गया क्षेत्र हरियाणा उद्योग विभाग द्वारा अधिग्रहित किया गया था , जिसके लिए 15.11.2008 को एक निर्णय की घोषणा की गई थी।वास्तव में , याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ' पिछली अधिग्रहण कार्यवाही ' को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2010 के फैसले के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।इसलिए याचिकाकर्ताओं ने 09.04.2012 दिनांकित आदेश की समीक्षा के लिए 14.05.2012 पर एक आवेदन दायर किया , जिसके संदर्भ में CLU के लिए आवेदन खारि ज कर दिया गया था।याचिकाकर्ताओं के पुनरीक्षण आवेदन को 29.01.2013 को खारिज कर दिया गया था।याचिकाकर्ता ने अपने समीक्षा आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ पीड़ित होकर हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव के समक्ष एक अपील दायर की , जिसे तीन महीने की अवधि के भीतर एक नए निर्णय के लिए निदेशक हरियाणा और टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग को 01.10.2013 को वापस भेज दिया गया।

(9) इस अवधि के दौरान भारत सरकार ने 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013' ('नया 2013 अधिनियम'-संक्षेप में) को लागू क रने के लिए 'नियत तिथि ' के रूप में दिनांक 01.01.2014 को अधिसूचित

किया।हरियाणा सरकार ने यह महसूस करते हुए कि नए 2013 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय निहितार्थ बहुत बोझिल और महंगे होंगे, पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी की। याचिका कर्ताओं के अनुसार, हरियाणा सरकार का उक्त अधिनियम, नए 2013 अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिम्मेदारियों से बाहर निकलने के लिए केवल एक चाल थी।

(10) आरोप है कि हरियाणा सरकार ने एक बार फिर पुराने 1894 अधिनियम के तहत कम दर पर भूमि अधिग्रहण करने के अपने दुर्भावनापूर्ण इरादों को दर्शाते हुए 28-10-2013 को 1894 अधिनियम पुराने की खंड 4 के तहत एक नई अधिसूचना जारी की।

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए याचिकाकर्ताओं के 50 प्रतिशत शेयरों सहित कुल 43.09 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए । औद्योगिक विकास केंद्र , साहा और एकीकृत औद्योगिक परिसर , साहा का विकास।

(11) याचिकाकर्ताओं ने 26-11-2013 को पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी दिनांक 28.10.2013 की अधिसूचना के खिलाफ पुराने अधिनियम की धारा 5 (ए) के तहत अपनी आपत्तियां दायर की। इस आशय पर एक विशिष्ट आपत्ति जताई गई कि विवादित अधिसूचना याचिकाकर्ताओं के कानूनी और मूल्यवान अधिकारों को विफल करने के एकमात्र उद्देश्य से जल्दबाजी में जारी की गई थी।इसके अलावा, अन्य आपत्तियां भी उठाई गईं जिनमें उन्होंने सी. एल. यू. के लिए आवेदन किया था। यह भी कहा गया कि उनके सी. एल. यू. आवेदन विचाराधीन अभी भी निदेशक, नगर और देश योजना विभाग, हरियाणा के समक्ष विचाराधीन है।हालाँकि 31-01-2014 को हरियाणा नगर और ग्राम योजना विभाग के निदेशक ने इस आधार पर याचिकाकर्ताओं के आवेदन को फिर से खारिज कर दिया कि उनकी भूमि को फिर से हासिल कर लिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. एल. यू. के लिए पहले के आवेदन को इस गलत आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उनकी भूमि 'पिछली अधिग्रहण कार्यवाही' के तहत अधिग्रहित की गई थी, जबकि वास्तव में इस न्यायालय द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।

(12) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नया 2013 अधिनियम 01.01.2014 को लागू हुआ और उस समय तक पुराने 1894 अधिनियम के तहत कोई निर्णय पारित नहीं किया गया था, जो किसी भी मामले में नए 2013 अधिनियम की खंड 114 के आधार पर निरस्त हो गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होने के लिए 29.01.2014 को नोटिस जारी किए गए थे ताकि 26.11.2013 पर दायर उनकी आपत्तियों पर विचार किया जा सके।भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 18.03.2014 को साहा, ढकोला, टेपला, जवाहरगढ़, बिठा और शेरगढ़ गावों में भूमि अधिग्रहण के संबंध में याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ तैंतीस अन्य लोगों द्वारा दायर आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए एक ही आदेश/रिपोर्ट पारित की।भूमि मालिकों द्वारा की गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने पुराने 1894 अधिनियम को निरस्त करने के संबंध में आपत्तियों को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए एक प्रश्न पर, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 05-08-2014 को पर जवाब दिया कि श्रीमती मधु अग्रवाल और श्रीमती सुनीता अग्रवाल के संबंध में 'पिछली अधिग्रहण कार्यवाही' कायम रहेगी और वर्तमान अधिग्रहण कार्यवाही याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू होगी। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विवादित भूमि के संबंध में कोई विभाजन कार्यवाही किए बिना, प्रतिवादी ने अत्यवस्थित तरीके से भूमि के अलग–अलग अधिग्रहण कार्यवाही केतहत अलग–अलग मालिको से भूमि के एक टुकड़े का अधिग्रहण करने की मांग की।

(13) इसके बाद 27-10-2014 को हरियाणा सरकार ने याचिकाकर्ताओं सहित 39.27 एकड़ भूमि के संबंध में पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत एक अधिसूचना जारी की।याचिकाकर्ताओं की पत्नियों , श्रीमती मधु अग्रवाल और श्रीमती सुनीता अग्रवाल ने इस न्यायालय में 2015 की सी. डब्ल्यू. पी. No.1796 नामक एक रिट याचिका दायर की , जिसमें खंड 4 के तहत 23.12.2005 की 'पिछली अधिग्रहण' अधिसूचना और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत 29.12.2006 की घोषणा को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं की पत्नियों द्वारा याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि अधिसूचनाओं ने नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (2) को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को निरस्त कर दिया था। वास्तव में वे रिट याचिका दायर करने के लिए विवश थे क्योंकि 2008 की पिछली रिट याचिका यानी सी . डब्ल्यू. पी. No.1048 जिसे 16.12.2010 को अनुमति दी गई थी , केवल उस विशेष रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं के संबंध में थी।हालाँकि, प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं की पत्नियों के संबंध में पहले

के अधिग्रहण को वैध मान रहे थे।इस न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका (2015 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1796 में 02.02.2015 पर प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी; इसके अलावा, अधिग्रहित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था।

(14) याचिकाकर्ता अब पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 28.10.2013 और घोषणा दिनांक 27.10.2014 पर हमला करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी 28-10-2013 की अधिसूचना 01-01-2014 को नए 2013 अधिनियम के लागू होने से दो महीने से भी कम समय पहले जारी की गई थी।वास्तव में पुराने 01-01-2014 से पहले 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत अंतिम घोषणा को प्रकाशित करने के लिए कोई समय नहीं बचा था।याचिकाकर्ताओं के अनुसार पुराने 1894 अधिनियम के तहत खंड 4 अधिसूचना उन्हें नए कानून यानी नए 2013 अधिनियम के तहत लाभ लेने से रोकने के लिए एक चाल थी। प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अधिग्रहण कार्यवाही और कुछ नहीं बल्कि शक्ति का एक रंगीन प्रयोग है।एक कार्य अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से और किसी अन्य तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।इसलिए, चूंकि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत दिनांक 28.10.2013 की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद किसी भी तरह से भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था, इसलिए नए 2013 अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण करना ही एकमात्र वैध तरीका था। इसलिए, प्रतिवादी के लिए यह अनिवार्य था कि वे उक्त पाठ्यक्रम का पालन करें।इसके अलावा, नियत दिन यानी 01-01-2014 को नए 2013 के हुआ था, पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत कोई घोषणा जारी नहीं की गई थी।इसलिए, वर्तमान अधिग्रहण कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं था।

नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) का पढने से ऐसी स्थिति का पता चलता है जहां अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होने के करीब थी, लेकिन पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत कोई 'अवार्ड' तब तक नहीं दिया गया था जब तक कि नया 2013 अधिनियम 01.01.2014 को लागू नहीं हुआ था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके पीछे का उद्देश्य

निस्संदेह पुराने 1894 अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण के संबंध में अंतिम घोषणा को बचाना था, जिसमें कोई अवार्ड पारित नहीं किया गया था।नए 2013 अधिनियम की खंड 114 का भी उल्लेख किया गया है जो पुराने 1894 अधिनियम को निरस्त करती है। इस प्रकार , निर्धारित तिथि यानी 01.01.2014 के बाद, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अधिग्रहण कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती थी ।

(15) प्रतिवादी को 26.03.2015 को प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी और इस बीच यथास्थिति, यह आदेश दिया गया था , सुनवाई की तारीख तक बनाए रखी जाएगी , जिसे 30.04.2015 पर जारी रखने का आदेश दिया गया था।

(16) प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एक लिखित बयान हरियाणा सरकार , उद्योग और वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री परवेश कुमार द्वारा दायर किया गया है , जो अपनी आधिकारिक क्षमता में मामले के तथ्यों से अच्छी तरह से परिचित हैं और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिकृत हैं।

(17) याचिकाकर्ताओं और उनकी पत्नियों द्वारा पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत अधिग्रहण कार्यवा ही और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा उनके निपटारे के लिए दायर आपत्तियों का उल्लेख किया गया है।अंबाला के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने यह प्रस्तुत किया है याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार किया और भूमि अधिग्रहण के लिए सिफारिश की क्योंकि स्थल पर भूमि खाली पड़ी थी।हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ('एच. एस. आई. आई. डी. सी.'-संक्षेप में) ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, अंबाला की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की।राज्य सरकार ने अंबाला के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर की सिफारिशों और एच . एस. आई. आई. डी. सी. की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया और इसे पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत जारी दिनांक 27.10.2014 की घोषणा में शामिल किया गया था।

(18) यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत दिनांक 1 की अधिसूचना किसी भी तात्कालिकता या जल्दबाजी में जारी नहीं की गई थी क्योंकि इसके बाद योजना, प्रक्रिया और प्रक्रिया की एक श्रृंखला का पालन किया गया था।सरकार वास्तव में तात्कालिक प्रावधानों को लागू करते हुए एक अधिसूचना जारी करने के अपने अधिकार के भीतर हो सकती है , जो कि मामला नहीं था। भूमि अधिग्रहण की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए भूमि

को अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने के निर्णय से पहले बहुत सारे जमीनी कार्य और तैयारी करनी होती है।

491

और अन्य (S.S.Saron, J.)

पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना प्रकाशित करने से पहले, जो उस समय मौजूद थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी की गई अधिसूचना दिनांक 08.10.2013 की वैधता या स्थिरता की व्यापक परिप्रेक्ष्य में जांच की जानी चाहिए।

(19) राज्य सरकार द्वारा पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी की गई अधिसूचना दिनांक 23.12.2005 की गाँव ढकोला, साहा, टेपला और जवाहरगढ़, तहसील साहा जिला अंबाला की 278 एकड़, 1 कनाल, 1 मरला भूमि के अधिग्रहण या विकास केंद्र , साहा चरण II, तहसील साहा, जिला अंबाला की स्थापना के लिए थी। राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर , अंबाला की सिफारिशों और एच. एस. आई. आई. डी. सी. की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत दिनांक 29.12.2006 की घोषणा जारी की गई थी।

(20) उक्त अधिग्रहण कार्यवाही से व्यथित होकर, कई भूमि मालिकों ने राज्य सरकार के समक्ष अपनी संरचनाओं जैसे आवासीय घरों , दुकानों, धार्मिक भवनों आदि को जारी करने के लिए अभ्यावेदन दिया। तदनुसार , यह देखा गया कि संरचनाओं वाले भूमि के कुल खंडों को अधिग्रहण से मुक्त किया जा सकता है।राज्य सरका र ने पुराने 1894 अधिनियम की खंड 48 के तहत दिनां 25.07.2008 को गाँव ढकोला, साहा और टेपला, तहसील साहा, जिला अंबाला में 28 एकड़, 1 कनाल, 10 मरले की भूमि जारी करने के लिए अधिसूचना जारी की। अवार्ड की घोषणा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, अंबाला द्वारा 15.11.2008 को की गई थी।इस प्रकार, अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी कर ली गई और भूमि का कब्जा ले लिया गया , सिवाय इसके कि जहां इस न्यायालय द्वारा बेदखल करने पर रोक लगा दी गई थी।

(21) अपनी भूमि के अधिग्रहण से व्यथित विभिन्न भूमि मालिकों ने रिट याचिकाओं के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं ने 2008 का सी. डब्ल्यू. पी. No.1048 भी दायर किया जिसका शीर्षक था 'दीपक अग्रवाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' जो उनकी भूमि को जारी करने की मांग कर रहा था।भूमि अधिग्रहण से संबंधित

अन्य याचिकाओं के एक समूह के साथ उक्त याचिका को इस न्यायालय द्वारा दीपक अग्रवाल के मामले सी. डब्ल्यू. पी. No.1048/2008 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2010 को अनुमति दी गई थी। दिनांकित 16.12.2010 आदेश का परिचालन भाग निम्नानुसार हैः-

"तदनुसार, हम इन रिट याचिकाओं को (2009 के सी. डब्ल्यू. पी. No.108 को छोड़कर) उन याचिकाकर्ताओं को छोड़कर सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को अनुमति देते हैं जिन्होंने अधिनियम की खंड 5-ए के तहत आपत्तियां दायर नहीं की हैं और उन लोगों को भी जिन्होंने अधिग्रहण के तहत भूमि के लिए मुआवजे को स्वीकार किया है और विवादित अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया है।

हालाँकि, कानून के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता राज्य के पास रहेगी।"

(22) 2008 के दीपक अग्रवाल के मामले सी. डब्ल्यू. पी. No.1048 में [कुछ याचिकाकर्ताओं ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं।

सर्वोच्च न्यायालय दीपक अग्रवाल के मामले सी. डब्ल्यू. पी. No.1048 में शीर्षक 'देविंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और

अन्य '।2011 के एस. एल. पी. (सी) No.27987-988 में, यथास्थिति का आदेश दिनांकित 26.09.2011 के आदेश के संदर्भ में दिया गया था जो इस प्रकार हैः-

"इस बीच पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है जैसा कि आज प्राप्त हो रहा है।इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि कोई भी पक्ष संपत्ति के वर्तमान स्वरूप को नहीं बदलेगा या उसे किसी भी तरह से किसी से अलग नहीं करेगा।"

(23) राज्य सरकार ने उक्त एस . एल. पी. में अपना जवाबी-हलफनामा दिनांक 05.09.2012 दाखिल किया जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

(24) इस बीच भूमि अधिग्रहण कलेक्टर , अंबाला ने दिनांकित 01.06.2012 पत्र के संदर्भ में भूमि के अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो पहले से ही अधिग्रहित भूमि का हिस्सा था vide अवार्ड दिनांक 15.11.2008 । यही कारण था कि इस न्यायालय ने 2008 के दीपक अग्रवाल के मामले सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1048 का निपटारा करते हुए कानून के अनुसार, यदि आवश्यक हो , तो विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राज्य के साथ रहने की स्वतंत्रता दी थी।यह भी कहा गया कि अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि को 2008 के दीपक अग्रवाल के मामले सी . डब्ल्यू. पी. संख्या 1048 और अन्य संबंधित मामलों में इस अदालत के आदेश को देखते हुए जा री किया गया था। इसके बाद, एच. एस. आई. आई. डी. सी. ने पत्र दिनांक 12-07-2012 के 1 पत्र के माध्यम से उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि इस न्यायालय द्वारा जारी की गई भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता थी क्योंकि अधिकांश भूमि सड़क परिसंचरण, हरित पट्टियों और आंतरिक योजना प्रस्तावों के लिए आवश्यक थी ; इसके अलावा, बचे हुए क्षेत्र एच . एस. आई. आई. डी. सी. के योजना प्रस्तावों को प्रभावित कर रहे थे और सड़क के बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध कर रहे थे।हालांकि, उद्योग और वाणिज्य विभाग के कार्यालय ने दिनांक 13-09-2012 के पत्र के माध्यम से एच. एस. आई. आई. डी. सी. से कानूनी दृष्टिकोण से मामले की फिर से जांच करने का अनुरोध किया क्योंकि उसने एक ओर 2008 के दीपक अग्रवाल के मामले सी . डब्ल्यू. पी. संख्या 1048 में दिनांक 16-12-2010 के आदेश के खिलाफ समीक्षा आवेदन दायर किए थे, जो अभी भी इस अदालत में लंबित थे , और दूसरी ओर, वह भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव भेज रहा था।इस बीच , इस न्यायालय द्वारा 02.11.2012 दिनांकित आदेश के माध्यम से समीक्षा आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने एक बार फिर हरियाणा राज्य आई . डी. सी. से दिनांक 20-02-2013 के पत्र के माध्यम से इस अदालत के आदेश को ध्यान में रखते हुए मामले की फिर से जांच करने का अनुरोध किया है।

493

और अन्य (S.S.Saron, J.)

एच. एस. आई. आई. डी. सी. ने दिनांकित 09.09.2013 पत्र के माध्यम से सू चित किया कि उसने रिट याचिकाओं के संबंध में 2008 के दीपक अग्रवाल के मामले सी . डब्ल्यू. पी. संख्या

1048 में दिनांकित 16.12.2010 के आदेश को चुनौती नहीं दी , जहां दिनांकित 23.12.2005 और 29.12.2006 की अधिसूचनाएं रद्द कर दी गई थीं।हालाँकि, यह अनुरोध किया गया था कि मामले में तेजी लाई जाए क्योंकि इस न्यायालय द्वारा जारी की गई भूमि विकास केंद्र , साहा के चरण I और II की संशोधित लेआउट योजना के अनुसार सड़क परिसंचरण , हरित पट्टियों और आंतरिक योजना प्रस्ताव के लिए आवश्यक थी।

(25) यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस पृष्ठभूमि में अधिसूचनाओं का वर्तमान सेट, यानी खंड 4 के तहत अधिसूचना 28-10-2013 और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा दिनांक 27.10.2024 जारी की गई थी ताकि एक सरकारी परियोजना में बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जा सके जिसके लिए वर्ष 2005 में अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी।इसलिए , विषय भूमि का अधिग्रहण करना रातोंरात लिया गया निर्णय नहीं था।

(26) 2013 के नए अधिनियम की खंड 24 (1) और खंड 114 का संदर्भ दिया गया है , जो डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2014 से लागू हुई थी।सामान्य खंड अधिनियम, 1897 ('1897 जी. सी. अधिनियम'-संक्षेप में) की खंड 6 का भी संदर्भ दिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से पता चलेगा कि यदि याचिकाकर्ताओं के दावे की जांच उसके आलोक में की जाती है , तो यह एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि केवल इसलिए कि पुराने 1894 के अधिनियम की खंड 4 के तहत कार्यवाही केवल 28.10.2013 पर एक अधिसूचना जारी करके शुरू की गई थी , इन्हें नए 2013 के अधिनियम के लागू होने पर 01.01.2014 पर समाप्त नहीं माना जाएगा। इसलिए , इसके बाद नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई कार्यवाही शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(27) यह कहा जाता है कि संसद अपने विवेक से ऐसी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी जिसमें नए 2013 अधिनियम को लागू करते समय दिनांक 01.01.2014 नए 2013 अधिनियम से पहले पुराने 1894 अधिनियम के तहत कई कार्यवाहियां शुरू की जा चुकी हैं और इस तरह की कार्यवाहियों का भविष्य क्या होगा।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि संसद ने नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) को लागू करके स्पष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान की है। संसद की मंशा को स्पष्ट रूप से यह कहते हुए घोषित किया गया था कि ऐसे सभी मामलों में जहां नए 2013 अधिनियम के लागू होने से पहले पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी , ऐसे मामलों में जहां अवार्ड पारित नहीं किए गए थे, उस स्थिति में भूमि मालिक को नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों का लाभ मिलेगा। ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति नए 2013 अधिनियम के

प्रावधान और पुराने 1894 अधिनियम के तहत नहीं होगी । यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के प्रावधानों में 'आरंभ' के बजाय 'पूर्ण' जैसे शब्द को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(28) यह कहा गया है कि संसद ने नए 2013 के अधिनियम की खंड 24 (1) में 'शुरू की गई' अभिव्यक्ति का जानबूझकर उपयोग किया है और उक्त अभिव्यक्ति न केवल जानबूझकर की गई है, बल्कि यह स्पष्ट भी है और इसमें स्पष्टीकरण की कोई अंतर्निहित कमी नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संसद ने जहां भी आवश्यक हो , उचित और उचित स्पष्टीकरण के साथ नए 2013 अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों को लागू किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत दिनांक 28-10-2013 की अधिसूचना जारी करना नए 2013 अधिनियम की प्रयोज्यता के बहुत करीब नहीं कहा जा सकता है और इ स तरह, कार्यवाही को नए 2013 अधिनियम की प्रयोज्यता पर समाप्त नहीं कहा जा सकता है। यदि खंड 24 (1) को अधिनियमित करते समय या नए 2013 अधिनियम की खंड 114 के निरसन प्रावधानों को सम्मिलित करते समय संसद का यही इरादा होता , तो उस स्थिति में ऐसा प्रावधान विधायिका द्वा रा प्रदान किया जाता।वास्तव में , विधायिका ने केवल नए 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान का लाभ सुनिश्चित करने के लिए 01.01.2014 की कट-ऑफ तिथि प्रदान की और पुरानी 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई ऐसी कार्यवाही के समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं है। यह भी प्र स्तुत किया जाता है कि नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) और खंड 24 (2) दोनों में 'अवार्ड' अभिव्यक्ति का उपयोग एक निश्चित घटना के लिए है क्योंकि अन्य अभिव्यक्तियाँ अस्पष्ट और गैर -विशिष्ट होंगी।नए 2013 अधिनियम के लागू होने का मतलब यह नहीं है कि नए 2013 अधिनियम के लागू होने पर भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का कार्यालय काम करना बंद कर देगा , क्योंकि खंड 9 के तहत नोटिस और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत 'अवार्ड' पारित करने के अलावा, यहां तक कि संदर्भ देना भी भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।यदि संसद ने नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) में 'अवार्ड' के अलावा कोई अन्य अभिव्यक्ति दी होती जो अनिर्दिष्ट और अनिश्चित होती क्योंकि पुराने 1894 अधिनियम के तहत इस तरह से 'शुरू' की गई कार्यवाही के कई चरण हो सकते थे।

(29) श्री देवेंद्र पाल सिंह , डिवीजनल टाउन प्लानर , एच. एस. आई. आई. डी. सी., पंचकूला (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा भी लिखित बयान दायर किया गया है।यह कहा गया है कि

याचिकाकर्ता अपनी 5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की विवादित अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हैं, जिसमें उनकी पत्नियां कुछ भूमि में 50 प्रतिशत सह-भागीदार हैं।अंबाला जिले की तहसील साहा के गाँव टेपला में कुछ भूमि याचिकाकर्ताओं का संयुक्त स्वामित्व है।याचिकाकर्ताओं ने यह प्रस्तुत किया है अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हैं। विभिन्न आधारों पर पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी किया गया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिसूच ना नए 2013 अधिनियम के लागू होने से दो महीने से भी कम समय पहले जारी की गई थी , इसके अलावा, पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत कोई अधिसूचना अधिसूचित तिथि, यानी 01.01.2014 को या उससे पहले जारी नहीं की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दि या है कि नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) के तहत, विवादित अधिग्रहण को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे केवल ऐसे मामलों में बनाए रखा जा सकता है जहां कार्यवाही पूरी होने के करीब थी और 'अवार्ड' केवल तब पारित किए जाने थे जब नया 2013 अधिनियम लागू हुआ, यानी 01.01.2014 को, तो ऐसे मामलों में अधिग्रहण को बचाया जा सकता है।इसके अलावा , यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देते हुए आधार बनाया है कि नए 2013 अधिनियम की खंड 114 के तहत, एक बार पुराने 1894 अधिनियम को निरस्त कर दिए जाने के बाद पुराने 1894 अधिनियम में निर्धा रित विभिन्न जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए कोई तंत्र नहीं बचा था , जिसके कारण अधिग्रहण की कार्यवाही को बनाए नहीं रखा जा सका।

(30) इस संबंध में , प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) और खंड 114 के प्रावधान, जो 01.01.2014 से लागू हुए थे और साथ ही 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के प्रावधानों को जब संयुक्त रूप से पढ़ा जाएगा तो यह एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि केवल इसलिए कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत 28.10.2013 पर एक अधिसूचना जारी करके कार्यवाही शुरू की गई थी, इन्हें नए 2013 अधिनियम की प्रयोज्यता पर कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। यह कहा गया है कि संसद अपने विवेक से नए 2013 अधिनियम 01-01-2014 को लागू करते समय स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी कि नए 2013 अधिनियम के लागू होने से पहले ही पुराने 1894 अधिनियम के तहत कई कार्यवाहियां शुरू की जा चुकी हैं। इसके अलावा, ऐसी कार्यवाहियों का क्या भविष्य होगा, अर्थात वे कार्यवाहियां जो नए 2013 अधिनियम के लागू होने से पहले पुराने 1894 अधिनियम के तहत चल रही थीं।

(31) संक्षेप में, प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया जाना चाहिए कि नया 2013 अधिनियम 01-01-2014 का लागू होना किसी भी तरह से उन कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता है जो पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत शुरू की गई हैं और ये नए 2013 अधिनियम 01-01-2014 के लागू होने के बावजूद उक्त पुराने 1894 अधिनियम के तहत जारी रहना है।

(32) यह मामला इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के समक्ष 18.08.2015 को आया, जिस तारीख को मामले को पूर्ण पीठ को भेजने का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः-

"इस पी के समक्ष बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं सूचीबद्ध हैं।

2017(2)

जिसमें, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम') की खंड 6 के तहत घोषणा अधिनियम के निरसन के बाद और भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (संक्षेप में '2013 अधिनियम') में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार शुरू होने के बाद प्रकाशित की गई थी।कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना (ओं) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के निरसन से पहले आधिकारिक राजपत्र में प्रका शित की गई है , जबकि दैनिक समाचार पत्रों और /या इलाके में प्रकाशन 2013 अधिनियम के प्रारंभ के बाद किया गया है। चूँकि उठाया गया मुद्दा महत्वपूर्ण है, विशुद्ध रूप से कानूनी है और बड़ी संख्या में मामलों में अक्सर उत्पन्न होता है , इसलिए हम एक बड़ी पीठ द्वारा निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को संदर्भित करना उचित समझते हैंः-

1. क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की खंड 4 के तहत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, लेकिन बाद में उचित मुआवजे का अधिकार शुरू होने के बाद समाचार पत्रों में भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास और पु नर्स्थापन में पारदर्शिता अधिनियम , 2013 01.01.2014 को कानूनी रूप से टिकाऊ है?

2. क्या अधिनियम की खंड 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई और अधिनियम की खंड 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की अनुमति भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के निरसन के बाद स्वीकार्य और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रारंभ के बाद

जल्द से जल्द एक बड़ी पीठ के गठन के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखे जाने चाहिए।

चूंकि इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाले बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, इसलिए हम किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को बड़ी पीठ की सहायता करने की स्वतंत्रता देते हैं।"

(33) उपरोक्त संदर्भ के संदर्भ में , यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत प्रकाशित अधिसूचना , लेकिन 01.01.2014 को नए 2013 अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद समाचार पत्र में बाद में प्रकाशित , कानूनी रूप से टिकाऊ है। इसके अलावा, क्या खंड 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई और अधिसूचना का प्रकाशन

पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत पुराने 1894 अधिनियम के निरसन के बाद और नए 2013 अधिनियम के प्रारंभ के बाद 01.01.2014 से अनुमति है।

(34) उठाए गए तर्कों के संदर्भ में , यह भी विचार करने के लिए बाध्य है कि पुराने 1894 अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही को कब और किस स्तर पर 'शुरू' किया जा सकता है ताकि नए 2013 अधिनियम के लागू होने के बाद इसे जारी रखा जा सके या नहीं।

(35) श्री नितिन सरीन , श्री रितेश अग्रवाल , सुश्री अंकिता संब्याल और श्री शक्ति सिंह , अधिवक्ताओं के साथ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम . एल. सरीन ने जोरदार तर्क दिया है कि नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) और नए 2013 अधिनियम की खंड 114 के स्पष्ट जनादेश को देखते हुए पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा, नए 2013 अधिनियम की खंड 114 (2) को ध्यान में रखते हुए पुराने 1894 अधिनियम का निरसन 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के सामान्य अनुप्रयोग को प्रभावित या प्रभावित करने के लिए नहीं है। विशेष रूप से 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के खंड (सी) का एक विशिष्ट संदर्भ दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नया 2013 अधिनियम लाभकारी विधान का एक हिस्सा है जिसमें कई लाभकारी प्रावधान हैं जो उन भूमि मालिकों के पक्ष में लागू किए जाने और प्रभावी किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं जिनकी भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की जानी है।यह प्रस्तुत किया जाता है

कि पुराना 1894 अधिनियम दो भागों में था, अर्थात धारा 4 से 17 जो इस बात से संबंधित है कि अधिग्रहण कैसे किया जाना है और धारा 8 से 28 कि क्षतिपूर्ति कैसे की जानी है।अतीत से एकदम अलग, नया 2013 अधिनियम, चार भागों में अधिनियमित किया गया है , अर्थात। अध्याय II जो 'सामाजिक प्रभाव और सार्वजनिक उद्देश्य के निर्धारण' से संबंधित है; अध्याय III 'खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधानों' से संबंधित है, अध्याय IV अधिसूचनाओं और अधिग्रहण से संबंधित है और अध्याय V से VIII 'पुनर्वास और पुनर्वास अवार्ड' से संबंधित है; 'पुनर्स्थापना और पुनर्वास की प्रक्रिया और तरीका '; 'पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति' और 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना '।नए 2013 अधिनियम के इन लाभकारी प्रावधानों को उन भूमि मालिकों के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। 'सामाजिक प्रभाव' और 'सार्वजनिक उद्देश्य' के निर्धारण के संबंध में नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों पर काफी जोर दिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है , जिसे प्रस्तुत किया जाता है , जिसे निरस्त पुराने 1894 अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा , यह प्रस्तुत किया जाता है कि नए 2013 अधिनियम को 26.09.2013 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना इसके तुरंत बाद 28.10.2013 को प्रकाशित की गई थी। याचिकाकर्ताओं के माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यह जल्दबाजी में किया गया था ताकि उन भूमि मालिकों को नए 2013 अधिनियम के लाभ से वंचित किया जा सके जिनकी भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था।नए 2013 अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए नियत दिन 01.01.2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। (36) श्री सरीन ने बाबू बरक्या ठाकुर बनाम बॉम्बे राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर यह तर्क देने के लिए मजबूत निर्भरता रखी है कि पुराने 1894 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा की तारीख से 'शुरू' की गई है। वर्तमान मामले में , पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा की तारीख 27.10.2014 है और उक्त तारीख को नया 2013 अधिनियम अर्थात् 01.01.2014 से प्रभावी हुआ था।इसलिए, पुराने 1894 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को नए 2013 अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले 'शुरू' नहीं कहा जा सकता है ताकि नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के प्रावधानों को लागू किया जा सके और अधिग्रहण की कार्यवाही

जारी रखी जा सके।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी कर ने को यानि 28.10.2013 को पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही की 'शुरुआत' की तारीख के रूप में नहीं लिया जा सकता है , जो केवल प्रारंभिक उद्देश्य के लिए है।रिलायंस को भजन सिंह बनाम पंजाब राज्य पर भी रखा गया है। इसलिए, माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सरीन के अनुसार, पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

(37) अधिवक्ता सुश्री मन्नू चौधरी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शैलेंद्र जैन ने 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 पर दृढ़ता से भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि उक्त प्रावधान प्रकृति में सामान्य है और सार्वभौमिक रूप से लागू होता है।यह वर्तमान मामले में हर मामले में लागू होना है।वास्तव में श्री जैन के अनुसार, यह केवल उक्त प्रावधान है जो पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की स्थिरता या निरंतरता को निर्धारित करने के लिए है और क्या खंड 4 के तहत उक्त अधिसूचना को नए 2013 अधिनियम के तहत फिर से अधिनियमित माना जाता है। भूमि अधिग्रहण के संबंध में निरसन की तारीख से पहले पुराने 1894 अधिनियम की खंड 3 (एफ) के साथ पठित खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना को इसे जारी रखने के लिए नए 2013 अधिनियम की खंड 2 (1), 3 (जेडए), 4 से 8 और 11 के पुनः अधिनियमित प्रावधानों के खिलाफ खड़ा किया जाना है और इसे बनाया गया या बनाया गया माना जाना चाहिए।

1 ए आई आर 1960 एससी 1203

2 (2014-4) पीएलआर 406 (पी एंड एच) (डीबी)

नए 2013 अधिनियम के संदर्भ में इस प्रकार पुनः अधिनियमित प्रावधानों के तहत जारी किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि इस तरह की कवायद की जाती है और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन नए 2013 अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के खिलाफ किया जाता है , तो संशो धित और वास्तव में नए 2013 अधिनियम में कई परिवर्धनों के माध्यम से अधिनियमित किए गए नए प्रावधानों के कारण दोनों के बीच कई विसंगतियां देखी जाएंगी।

(38) यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 (1) के तहत इसके निरसन से पहले प्रारंभिक अधिसू चना जारी की जाती है , जो नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है , तो इसे नए 2013 अधिनियम की खंड 11 के प्रावधानों के

तहत बनाया या जारी किया गया माना जाएगा। इसलिए , 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 के आधार पर , इसे नए 2013 अधिनियम की खंड 12 से 19 के संशोधित प्रावधानों के तहत किया जाएगा, जिसमें नए 2013 अधिनियम की खंड 2 (1) सहित कई परिवर्धन शामिल हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 (1) के तहत जारी एक अधिसूचना को आगे बढ़ाते हुए , ये नए 2013 अधिनियम की खंड 12 से 19 के प्रावधानों के तहत जारी किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं , जो पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना की तैयारी से संबंधित अधिक विस्तारित संशोधित प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं।इसलिए , निरस्त पुराने 1894 अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही को जारी रखना नए 2013 अधिनियम के शुरू होने पर 01.01.2014 को इसके निरसन के बाद अस्वीकार्य होगा।

(39) श्री पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री प्रतीक गुप्ता, अधिवक्ता के साथ 'दिवयुग रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. No.8963 प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता दो गाँवों, अर्थात् हरसरू और गढ़ी हरसरू में फैली 113 कनाल 1 मरले की भूमि का मालिक है, जिसमें वह क्रमशः 84 कनाल 18 मरले और 28 कनाल 3 मरले का मालिक है। उसी के राजस्व रिकॉर्ड को रिकॉर्ड में रखा गया है।प्रतिवादी ओ ने याचिकाकर्ता द्वारा धारण की गई कुल भूमि का 56 कनाल 1 मरला अधिग्रहण करने की मांग की।उनके मामले में पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत पहली अधिसूचना राजपत्र में 27.12.2013 को प्रकाशित की गई थी। पुराना 1894 अधिनियम 01.01.2014 से नए 2013 अधिनियम के प्रभाव में आने के साथ निरस्त हो गया।राजपत्र में इसके प्र काशन के बाद पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना समाचार पत्र में 01.01.2014 को प्रकाशित की गई थी। यह उक्त तिथि है जब नया 2013 अधिनियम लागू हुआ।

(40) याचिकाकर्ता दिवयुग रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड ने पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत 21.01.2014 को आपत्तियां दायर की।

पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत राजपत्र घोषणा 24.12.2014 को जारी की गई थी और घोषणा 23.12.2014 को समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी।श्री बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

मैसूर बनाम अब्दुल रज़ाक साहिब पर निर्भरता व्यक्त की वी. के. एम. कत्था इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य और यूजेनियो मिसक्विटा और अन्य बनाम गोवा राज्य और अन्य ।

(41) प्रतिष्ठित क्षेत्र के तहत एक ज़ब्ती कानून होने के कारण पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी अधिसू चना की अंतिम तिथि वह होनी चाहिए जिसमें इसे समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है।

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 12758 में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री पी . एस. खुराना ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम . एल. सरीन द्वारा की गई दलीलों को दोहराया है।

(42) राज्य की ओर से उपस्थित हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अमर विवेक ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई दलीलें बिना किसी आधार के हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि नए 2013 अधिनियम के लागू होने के साथ पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) और खंड 114 को देखते हुए किसी भी तरह से समाप्त नहीं होती है। अधिग्रहण की कार्यवाही पुराने 1894 अधिनियम के तहत 28.10.2013 को खंड 4 अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू की गई है , जो नए 2013 अधिनियम के प्रवर्तन के बावजूद उक्त पुराने 1894 अधिनियम के तहत जारी रहेगी। श्री विवेक के अनुसार, यह नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के प्रावधानों से स्पष्ट है , जिसमें यह प्रावधान है कि उक्त नए 2013 अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद , पुराने 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्य वाही के किसी भी मामले में , जहां पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत कोई अवार्ड नहीं दिया गया था, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित नए 2013 अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होने हैं ; इसके अलावा, जहां पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत एक अवार्ड दिया गया था, तो पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी रखी जानी चाहिए जैसे कि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया था।

(43) इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि 28.10.2013 को शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही के संबंध में कोई अवार्ड नहीं दिया जाता है, तो अधिक से अधिक मुआवजे का भुगतान

नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। तथ्य यह है कि नया 2013 अधिनियम लाभकारी विधान का एक हिस्सा है जिसमें कई लाभकारी प्रावधान हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है; हालाँकि, अंतराल अवधि में प्रदान किए गए वैधानिक प्रावधानों को लागू और प्रभावी किया जाना है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी करने और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत आपत्तियां दायर करने और 01.01.2014 से नए 2013 अधिनियम के प्रभावी होने के बाद , खंड 5-ए के तहत आपत्तियों का निर्णय भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 18.03.2014 को किया गया था।इसका मतलब यह होगा कि पुराने 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही नए 2013 अधिनियम के लागू होने के बाद भी जारी रहेगी ।

(44) बाबू बरक्या ठाकुर बनाम बम्बई राज्य (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय और भजन सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपर्युक्त) में इस न्यायालय का यह तर्क देने के लिए कि पुराने 1894 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा की तारीख से शुरू की गई है , यह कहा जाता है कि यह लागू नहीं होता है।अन्यथा भी, वह मजबूत स्थान रखता है

कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट), इलाहाबाद और अन्य बनाम राजा राम जयसवाल राजा राम बनाम एमपी राज्य और सखारबाई हरिभाऊ शेल्के बनाम एसडीओ।

(45) संक्षेप में, श्री विवेक प्रस्तुत करते हैं कि नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) के तहत 'आरंभ' शब्द का अर्थ अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण के संबंध में कार्यवाही को इसके दायरे में शामिल करना है जिसमें खंड 4 पुराने 1894 अधिनियम के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई थीं जो संक्षेप में अधिग्रहण की कार्यवाही की शुरूआत और शुरूआत है।

(46) नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) के साथ पठित खंड 114 के संयुक्त पठन से पता चलेगा कि नए 2013 अधिनियम के प्रवर्तन से पहले पुराने 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही किसी भी तरह से नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। यह केवल अस्थायी अवधि के लिए है कि नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) द्वारा विचार किए गए नए 2013 अधिनियम के अनुसार मुआवजा लागू होना है ताकि उन लोगों को अधिक लाभ दिया जा सके जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।वास्तव में , यह प्रस्तुत किया जाता है कि नए 2013 अधिनियम के प्रवर्तन के लिए नियत दिन यानी

01.01.2014 सचेत रूप से तय किया गया है ताकि उससे पहले की सभी कार्रवाइयों को बचाया जा सके।

(47) जहाँ तक श्री जैन, वरिष्ठ [6 एस. सी. सी. 1] द्वारा उठाए गए तर्कों का संबंध है।

7 2014 (1) एमपीएलजे 354 (एम. पी.)

8 2014 (6) एयर बम। आर. 257 (बॉम्बे) (डीबी)

1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 की प्रयोज्यता के संबंध में अधिवक्ता श्री विवेक ने प्रस्तुत किया है कि 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 के प्रावधान अधिग्रहण कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 को विशेष रूप से नए 2013 अधिनियम की खंड 114 (2) के संदर्भ में निरसन के प्रभाव के संबंध में लागू किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 और खंड 24 के संचालन में कुछ अतिव्यापी हो सकता है ; हालाँकि, खंड 6 को खंड 24 द्वारा ओवरराइड या ग्रहण नहीं किया गया है।श्री विवेक के अनुसार , खंड 6 लागू होती है और 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 निरस्त किए गए अधिनियमों के तहत जारी किए गए आदेशों , उप-कानूनों आदि को जारी रखने से संबंधित है और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से लागू किया गया है। 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6, जो प्रस्तुत की जाती है, निर्माण के सामान्य नियमों पर लागू होती है क्योंकि इस तरह से निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के तहत किए गए पिछले संचालन/कार्यों को बचाने के लिए जबकि 1897 के जी. सी. अधिनियम की खंड 24 अधिनियमों के तहत किए गए आदेशों, नियमों आदि के प्रावधानों पर लागू होती है।

(48) अन्यथा भी, यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 6 अनिवार्य रूप से कार्यकारी/प्रशासनिक कार्यों और अधिनियम के तहत प्रतिपादित सिद्धांतों के संबंध में किसी भी अधिनियम के तहत किए गए कार्यों से संबंधित आधार को शामिल करती है, जबकि 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 मुख्य रूप से प्रत्यायोजित /अधीनस्थ विधायी अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित है ताकि अधिनियम के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।श्री विवेक के अनुसार , 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 कार्यकारी और प्रशासनिक निर्णयों या अर्ध न्यायिक कार्यों पर लागू नहीं होती है।

(49) यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 प्रकृति में सामान्य है और सार्वभौमिक रूप से लागू होती है , लेकिन यह वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है।श्री जैन का यह तर्क कि यह केवल उक्त प्रावधान है जो पुराने 1894 अधिनियम की

खंड 4 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की स्थिरता या निरंतरता को निर्धारित करने के लिए है, सही स्थिति नहीं है।खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी करना और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा करना प्रशासनिक या कार्यकारी कार्य हैं न कि अर्ध - विधायी कार्य।कानून के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि खंड 4 के तहत जारी अधिसू चनाएं और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि जीवित रहने के लिए और ऐसा न करने पर, इन्हें मृत पत्र माना जा सके।यदि 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 को पुराने 1894 के अधिनियम के तहत लंबित कार्यवाही प र उनकी स्थिरता का परीक्षण करने के लिए लागू किया जाता है , तो श्री विवेक के अनुसार नए 2013 के अधिनियम की पूरी खंड 24 निरर्थक और अर्थहीन होगी, इसके अलावा, ऐसी व्याख्या विधियों की व्याख्या के हितकारी सिद्धांतों के विपरीत होगी।

जिसमें न्यायालय को नए 2013 अधिनियम की खंड 24 के साथ पठित खंड 114 के प्रावधानों को फिर से लिखना होगा। श्री विवेक के अनुसार संसद की ओर से लंबित कार्यवाही को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं था।

(50) वैकल्पिक रूप में यह प्रस्तुत किया जाता है कि नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) के साथ पठित खंड 114 के संयुक्त पठन से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलेगा कि नए 2013 अधिनियम के लागू होने से पहले पुराने 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है।

(51) याचिकाकर्ताओं की ओर से उ पस्थित माननीय अधिवक्ता द्वारा उठाई गई दलीलें मान्य नहीं हैं क्योंकि नए 2013 अधिनियम को लागू करके और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत पहले से शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त करने के लिए इसे 01.01.2014 से लागू करके संसद का कोई इरादा नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में पुराने 1894 अधिनियम के तहत खंड 4 अधिसूचना के चरण में अदालतें शायद ही कभी हस्तक्षेप करती हैं क्योंकि जो कुछ भी कहा जाना है वह भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत दायर आपत्तियों द्वारा अच्छी तरह से जांचा जा सकता है। आपत्तियों

पर विचार किया जा सकता है और एक आदेश पारित किया जा सकता है। इसलिए, माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार , खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होती है जो पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 में 'होगा' शब्द के उपयोग से स्पष्ट है। रिलायंस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुब चंद बनाम राजस्थान राज्य और राजा राम जयसवाल के मामले (उपरोक्त) में रखा गया है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जिस अस्थायी अवधि में पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 (1) के तहत अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, कार्यवाही जारी रखी जानी है और यदि कोई पुरस्कार पारित नहीं किया गया है, तो केवल मुआवजे का भुगतान नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है जो नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) का स्पष्ट इरादा है। श्री चेतन मितल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री उदित गर्ग, अधिवक्ता और श्री मयंक अग्रवाल अधिवक्ता, एच एस इाई आई डी सी के लिए उपस्थित होकर प्रस्तुत करते है कि

(52) हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश माननीय अधिवक्ता द्वारा उठाई गई दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है।पूर्ण पीठ को दिनांकित 18.08.2015 के आदेश के माध्यम से दिए गए संदर्भ का उत्तर उपरोक्त संहिताकरणों के आलोक में देने की आवश्यकता होगी।हालाँकि , उठाए गए तर्कों के आधार पर आगे के प्रश्नों पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी।संदर्भ आदेश के संदर्भ में जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना आवश्यक है और उठाए गए विवादों को निम्नानुसार फिर से तैयार किया जाता हैः

(1) क्या पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही को इसकी खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी करने के साथ 'शुरू' किया गया कहा जा सकता है या क्या यह केवल एक मंत्रिस्तरीय अधिनियम होगा और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन के साथ 'शुरू' कहा जा सकता है। यह नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के संदर्भ में है जो उक्त पुराने 1894 अधिनियम के तहत 'शुरू किए गए' भूमि अधिग्रहण के कुछ मामलों में पुराने 1894 अधिनियम के तहत प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रावधान करता है।

(2) क्या पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत 01-01-2014 के नियत दिन से पहले जारी की गई अधिसूचना खंड 6 को देखते हुए चालू रहेगी और किसी भी मामले में यह 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 के आधार पर अभी भी लागू रहेगी।

(3) क्या सरकारी राजपत्र में पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत प्रकाशित अधिसूचना, लेकिन बाद में समाचार पत्रों में प्रकाशित , यानी 01.01.2014 को नए 2013 अधिनियम के

प्रारंभ के बाद, कानूनी रूप से टिकाऊ है ; इसके अलावा, इनमें से कौन सी प्रभावी अधिसूचना होगी जिसके आधार पर प्रकाशन की प्रक्रिया को पूरा कहा जा सकता है, अर्थात क्या अधिसूचना शुरू में राजपत्र में प्रकाशित हुई है या बाद में अधिसूचना जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है।

(4) क्या खंड 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन इसके निरसन के बाद और नए 2013 अधिनियम के प्रारंभ के बाद 01.01.2014 से अनुमत है।

(53) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, नए 2013 अधिनियम को 26.09.2013 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।नया 2013 अधिनियम लागू होने की तारीख 01.01.2014 अधिसूचना दिनांक 19.12.2013 के माध्यम से थी।हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26.09.2013 को दी गई सहमति ने अधिकारियों को इस बात पर विचार करने और कल्पना करने के लिए पर्याप्त समय दिया कि नया 2013 अधिनियम लागू होना था और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना जल्दबाजी में 28.10.2013 को प्रकाशित की गई थी ताकि भूमि मालिकों को नए 2013 अधिनियम के लाभ से वंचित किया जा सके।

पहला प्रश्न दीपाक अग्रवाल और एन्नोर बनाम हरियाणा राज्य

505

और अन्य (S.S.Saron, J.)

(54) अधिग्रहण की कार्यवाही को कब 'आरंभ' कहा जा सकता है, इस बारे में पहले विवाद पर विचार करते हुए, पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 और 6 और नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) और 114 के प्रावधानों का संदर्भ दिया जा सकता है। पुराने 1894 के अधिनियम की खंड 4 और 6 इस प्रकार पढे-

“4. प्रारंभिक अधि सूचना और उस पर अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशनः - (1) जब भी [उपयुक्त सरकार] को यह प्रतीत होता है कि किसी भी इलाके में [की आवश्यकता है या] किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए [या किसी कंपनी के लिए] भूमि की आवश्यकता होने की संभावना है, तो उस आशय की एक अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में [और उस इलाके में प्रसारित होने

वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में , जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगी] प्रकाशित की जाएगी, और कलेक्टर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर देगा।

(2) इसके बाद यह किसी भी अधिकारी के लिए , या तो आम तौर पर या विशेष रूप से इस संबंध में ऐसी सरकार द्वारा अधिकृत , और उसके सेवकों और श्रमिकों के लिए विधिसम्मत होगा -

ऐसे इलाके में किसी भी भूमि पर प्रवेश करना और सर्वेक्षण करना और उसका स्तर लेना ; उप-मिट्टी में खुदाई करना या खो दना; यह पता लगाने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना कि क्या भूमि को ऐसे उद्देश्य के लिए अनुकूलित किया गया है;

प्रस्तावित भूमि की सीमाएँ और उस पर बनाई जाने वाली कार्य की इच्छित रेखा (यदि कोई हो) निर्धारित करना; ऐसे स्तरों, सीमाओं और रेखाओं को निशान लगाकर और खाइयों को काटकर चिह्नित करना; और,

जहाँ अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है और किसी भी खड़ी फसल , बाड़ या जंगल के किसी भी हिस्से को काटने और हटाने के लिए स्तर और सीमाएँ और रेखाएँ चिह्नित की जा सकती हैंः

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन में या किसी निवास-घर से जुड़े किसी संलग्न प्रांगण या बगीचे में (जब तक कि उस पर कब्जा करने वाले की सहमति के बिना) प्रवेश नहीं करेगा।

इससे पहले ऐसे कब्जाधारी को ऐसा करने के अपने इरादे के बारे में लिखित में कम से कम सात दिनों का नोटिस देना होगा।

6. घोषणा कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है।-

(1) इस अधिनियम, के भाग 7 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए [जब खंड 5ए, उप-खंड (2) के तहत की गई रिपोर्ट , यदि कोई हो , पर विचार करने के बाद [उपयुक्त सरकार] का यह समाधान हो जाता है कि कि सी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए किसी

विशेष भूमि की आवश्यकता है, तो ऐसी सरकार के सचिव या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उस आशय की घोषणा की जाएगी [और खंड 4, उप-खंड (1) के तहत एक ही अधिसूच ना द्वारा कवर की गई किसी भी भूमि के विभिन्न भागों के संबंध में समय -समय पर अलग -अलग घोषणाएं की जा सकती हैं , भले ही खंड 5ए, उप-खंड (2) के तहत एक रिपोर्ट या अलग -अलग रिपोर्ट (जहां भी आवश्यक हो) की गई हो। [बशर्ते कि धारा 4, 34 धारा (1) के तहत अधिसूचना द्वारा कवर की गई किसी विशेष भूमि के सम्बन्ध में कोई घोषणा नही 1(i) भूमि अधिग्रहण (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1967 (1967 का 1) के प्रारंभ के बाद , लेकिन भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ से पहले, तीन साल की समाप्ति के बाद किया जाएगा।

((ii) भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारंभ के बाद प्रकाशित किया अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किया जायगा।

[बशर्ते कि ऐसी कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी संपत्ति के लिए दिए जाने वाले मुआवजे का भुगतान किसी कंपनी द्वारा या पूरी तरह से या आंशिक रूप से सार्वजनिक राजस्व से या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी निधि से नहीं किया जाता है।

13 1923 के अधिनियम 38, खंड 4 द्वारा प्रतिस्थापित, "जब भी यह स्थानीय सरकार को दिखाई देता है" के लिए।

14 "प्रांतीय सरकार" के लिए ए. ओ. 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

15 1967 के अधिनियम 13 द्वारा प्रतिस्थापित, खंड 3, परंतुक के लिए 12.04.1967 से 1984 के अधिनियम 68, खंड 6 द्वारा प्रतिस्थापित, पहले परंतुक के लिए (24.09.1984 से 1967 के अधिनियम 13, खंड 3 द्वारा "बशर्ते कि" के लिए प्रतिस्थापित (12.04.1967 से

[स्पष्टीकरण 1.- पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी भी अवधि की गणना करने में , वह अवधि जिसके दौरान खंड 4, उप-खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसरण में की जाने वाली

किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर अदालत के आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है , को बाहर रखा जाएगा।

[स्पष्टीकरण 2.– जहाँ ऐसी संपत्ति के लिए दिए जाने वाले मुआवजे का भुगतान राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम की निधियों से किया जाना है , वहाँ ऐसे मुआवजे को सार्वजनिक राजस्व से भुगतान किया गया मुआवजा माना जाएगा]

(2) 19 [प्रत्येक घोषणा] सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, [और उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें भूमि स्थित है, जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगी , और कलेक्टर ऐसी घोषणा के सार की सार्वजनिक सूचना उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर देगा (ऐसे प्रकाशन की तारीख की अंतिम तारीख और ऐसी सार्वजनिक सूचना देना, जिसे इसके बाद घोषणा के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया गया है), और ऐसी घोषणा में कहा जाएगा कि जिला या अ न्य क्षेत्रीय विभाजन जिसमें भूमि स्थित है , जिस उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता है, उसका अनुमानित क्षेत्र, और जहां भूमि की योजना बनाई गई है, वह स्थान जहां ऐसी योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

(3) उक्त घोषणा इस बात का निर्णायक प्रमाण होगी कि भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या कंपनी के लिए है , जैसा भी मामला हो ; और ऐसी घोषणा करने के बाद , [उपयुक्त सरकार] इसके बाद दिखाई देने वाले तरीके से भूमि का अधिग्रहण कर सकती है।"

(55) नए 2013 अधिनियम की धारा 11,19,24 और 114 निम्नानुसार हैः-

"11. प्रारंभिक अधिसूचना और उस पर अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन। - (1) जब भी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है या इसकी आवश्यकता होने की संभावना है , तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिग्रहित की जाने वाली भू मि के विवरण के साथ उस आशय की एक अधिसूचना (जिसे इसके बाद प्रारंभिक अधिसूचना के रूप में संदर्भित किया गया है)

18 1984 के अधिनियम 68, खंड 6 द्वारा अंतःस्थापित (24.09.1984 से)

19 "घोषणा" के लिए 1967 के अधिनियम 13, खंड 3 द्वारा प्रतिस्थापित (12.04.1967 से 1984 के अधिनियम 68, खंड 6 द्वारा प्रतिस्थापित, "के लिए, और बताएगा" (24.09.1984) से

इसे निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा, अर्थात्:- (क) अधिकारिक राजपत्र में;

(ख) ऐसे क्षेत्र के इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनमें से एक क्षेत्रीय भाषा में होगा;

(ग) पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में स्थानीय भाषा में , जैसा भी मामला हो , और जिला कलेक्टर, उप-मंडल मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में;

(घ) उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करें;

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में, इस तरह से जो निर्धारित किया जा सकता है ।

(2) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद , ग्राम स्तर पर संबंधित ग्राम सभा या सभाओं , नगरपालिका क्षेत्रों के मामले में नगर पालिकाओं और संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों के मामले में स्वायत्त परिषदों को भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में उक्त उप-धारा के तहत जारी अधिसूचना की सामग्री के बारे में इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में सूचित किया जाएगा।

(3) उप-खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में शामिल सार्वजनिक उद्देश्य की प्रकृति , प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन की आवश्यकता के कारण , सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का सारांश और खंड 43 के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापना के उद्देश्यों के लिए नियुक्त प्रशासक के विवरण भी शामिल होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का कोई लेन -देन नहीं करेगा या ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लेकर इस अध्याय के तहत कार्यवाही पर विचार किए जाने तक ऐसी भूमि पर कोई बोझ नहीं डालेगाः

बशर्ते कि कलेक्टर , इस प्रकार अधिसूचित भूमि के मालिक द्वारा किए गए आवेदन पर , लिखित रूप में दर्ज की जाने वाली विशेष परिस्थितियों में , ऐसे मालिक को इस उप -धारा के संचालन से छूट दे सकता हैः

बशर्ते कि इस प्रावधान के जानबूझकर उल्लंघन के कारण किसी भी व्यक्ति को हुए नुकसान या चोट की भरपाई कलेक्टर द्वारा नहीं की जाएगी।

दीपक अग्रवाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

509

और अन्य (S.S.Saron, J.)

(5) उप-खंड (1) के तहत नोटिस जारी करने के बाद, कलेक्टर, खंड 19 के तहत घोषणा जारी करने से पहले, दो महीने की अवधि के भीतर निर्धारित भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने का कार्य करेगा और पूरा करेगा।

19. घोषणा का प्रकाशन और पुनर्वास और पुनर्स्थापना का सारांश।- (1) जब उपयुक्त सरकार को खंड 15 की उप-खंड (2) के तहत की गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि की आवश्यकता है , संतुष्ट किया जाता है, तो उस प्रभाव के लिए एक घोषणा की जाएगी , साथ ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के उद्देश्यों के लिए "पुनर्वास क्षेत्र" के रूप में पहचाने गए क्षेत्र की घोषणा , ऐसी सरकार के सचिव या अपने आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर के तहत की जाएगी और एक ही प्रारंभिक अधिसूचना द्वारा कवर की गई किसी भी भूमि के अलग-अलग पार्सल के संबंध में समय-समय पर अलग-अलग घोषणाएं की जा सकती हैं, भले ही एक रिपोर्ट या अलग-अलग रिपोर्ट (जहां भी आवश्यक हो) की गई हो।

(2) कलेक्टर उप-धारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना का सारांश प्रकाशित करेगाः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना का सारांश ऐसी घोषणा के साथ प्रकाशित नहीं किया जाता हैःबशर्ते कि इस उप-खंड के तहत कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि आवश्यक निकाय भूमि के अधिग्रहण की लागत के लिए पूरी या आंशिक रूप से राशि जमा नहीं करता है , जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित की जाएः

बशर्ते कि यह भी कि आवश्यक निकाय तुरंत राशि जमा करेगा ताकि उपयुक्त सरकार खंड 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर घोषणा प्रकाशित करने में सक्षम हो सके।

(3) परियोजनाओं में जहां भूमि का अधिग्रहण चरणों में किया जाता है , अधिग्रहण के लिए आवेदन स्वयं पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न चरणों को निर्दिष्ट कर सकता है , और सभी घोषणाएं इस प्रकार निर्दिष्ट चरणों के अनुसार की जाएंगी।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक घोषणा निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित किया गया , अर्थात्:- (क) अधिकारिक राजपत्र में;

(ख) उस इलाके में प्रसारित किए जा रहे दो दैनिक समाचार पत्रों में , जिनमें से एक क्षेत्रीय भाषा में होगा;

(ग) यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम में स्थानीय भाषा में और जिला कलेक्टर, उप-मंडल मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में;

(घ) उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करें;

(ङ) प्रभावित क्षेत्रों में, ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है।

(5) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक घोषणा दर्शाया जाएगा -

(क) जिला या अन्य क्षेत्रीय विभाजन जिसमें भूमि स्थित है;

(ख) जिस उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता है, उसका अनुमानित क्षेत्र और

(ग) जहाँ भूमि के लिए को ई योजना बनाई गई होगी , वह स्थान जहाँ ऐसी योजना का बिना किसी लागत के निरीक्षण किया जा सकता है।

(6) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा इस बात का निर्णायक प्रमाण होगी कि भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है और ऐसी घोषणा करने के बाद , उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट तरीके से भूमि का अधिग्रहण कर सकती है।

(7) जहां प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से बारह महीने के भीतर उप -धारा (1) के तहत कोई घोषणा नहीं की जाती है , तो ऐसी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया माना जाएगाः [बशर्ते कि

इस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में, कोई भी अवधि या अवधि जिसके दौरान किसी भी न्यायालय के आदेश द्वारा किसी रोक या निषेधाज्ञा के कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रुकी हुई थी, को बाहर रखा जाएगाः

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार बारह महीने की अवधि बढ़ाने की शक्ति है , यदि इसकी राय में परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो इसे उचित ठहराती हैंः

बशर्ते कि अवधि बढ़ाने के ऐसे किसी भी निर्णय को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और इसे अधिसूचित किया जाएगा और संबंधित प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

24. 1894 के अधिनियम संख्या 1 के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को कुछ मामलों में समाप्त माना जाएगा।-

(1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के किसी भी मामले में -

(क) जहां उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 11 के तहत कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे; या

(ख) जहां उक्त खंड 11 के तहत कोई अधिनिर्णय दिया गया है, तो ऐसी कार्यवाही उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी रहेगी , जैसे कि उक्त अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया है।

(2) उप-खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी , भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के मामले में , जहां उक्त खंड 11 के तहत एक अधिनिर्णय इस अधिनियम के प्रारंभ से पांच साल या उससे अधिक समय पहले किया गया है , लेकिन भूमि का भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है या मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है , तो उक्त कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा और उपयुक्त सरकार, यदि वह ऐसा चाहती है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करेगीः

बशर्ते कि जहां अधिनि र्णय दिया गया है और अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है , तो उक्त भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड

4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

114. निरस्त करें और बचत करें। - (1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 (1894 का 1) इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर , उप-खंड (1) के तहत निरसन को निरस्तीकरण के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम , 1897 (1897 का 10) की खंड 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा।" [(56) 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 निम्नानुसार हैः-

"6. निरसन का प्रभाव।- जहां यह अधिनियम, या कोई [केंद्रीय अधिनियम] या इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया विनियमन , अब तक किए गए या इसके बाद किए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है, तो जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक निरसन नही -

(1) ऐसी **किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित** करना जो निरसन प्रभावी होने के समय लागू नही थी या विधमान नही थी या

(2) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित करता है या उसके तहत कुछ भी विधिवत किया गया है या पीड़ित है; या

(3) इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के तहत अर्जित , उपार्जित या उपगत किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है; या

(4) इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में किए गए किसी दंड, ज़ब्त या सजा को प्रभावित करता है; या

(5) उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, दंड, ज़ब्त या सजा के संबंध में किसी भी जांच , कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है , और ऐसा कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित किया जा सकता है , जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्त या सजा लगाई जा सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था।"

(57) पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 में प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन का प्रावधान है और इसके बाद अधिकारियों को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं।यह प्रावधान किया गया है कि जब भी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना है, तो उस आशय की अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में और उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी चाहिए , जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। कलेक्टर को उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर दी जाने वाली ऐसी अधिसूचना का सार के बारे में सार्वजनिक सूच ना देनी है। ऐसे प्रकाशन की अंतिम तारीख और ऐसी सार्वजनिक सूचना देना , जिसे इसके बाद अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया जा रहा है।इस तरह की कवायद के बाद , किसी भी अधिकारी के लिए , या तो आम तौर पर या विशेष रूप से ऐसी सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत, और उसके सेवकों और श्रमिकों के लिए, ऐसे इलाके में किसी भी भूमि का सर्वेक्षण और स्तर लेना वैध होगा, उप-मिट्टी में खुदाई करना या बोर करना; यह पता लगाने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना कि क्या भूमि ऐसे उद्देश्य के लिए अनुकूलित है या नहीं ; लेने के लि ए प्रस्तावित भूमि की सीमाएँ और उस पर बनाने के लिए प्रस्तावित कार्य की इच्छित रेखा (यदि कोई हो) निर्धारित करना; ऐसे स्तरों, सीमाओं और रेखाओं को निशान लगाकर और खाइयों को काटकर चिह्नित करना; और, जहां अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है और स्तरों को लि या जा सकता है और सीमाएँ और रेखाएँ चिह्नित की जा सकती हैं , वहा किसी भी खडी फसल या जंगल के किसी भी हिस्से को काट कर साफ़ करना।परंतुक के संदर्भ में , किसी भी व्यक्ति को किसी भी भवन में या आवास से जुड़ी किसी भी संलग्न अदालत या बगीचे में प्रवेश नहीं करना है (जब तक कि उस पर कब्जा करने वाले की सहमति न हो) ऐसे कब्जा करने वाले को ऐसा करने के इरादे के बारे में कम से कम सात दिनों का लिखित नोटिस दिए बिना।

(58) पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत एक अधिसूचना के प्रकाशन का उद्देश्य भूमि का सर्वेक्षण करके यह पता लगाने का इरादा व्यक्त करना है कि क्या भूमि अधिग्रहण के लिए उपयुक्त है।खंड 4 की उप-खंड (2) के संदर्भ में, किसी भी अधिकारी के लिए, जो या तो आम तौर पर या विशेष रूप से ऐसी सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत है , और उसके सेवकों और श्रमिकों के लिए ऐसे इलाके में किसी भी भूमि के स्तर पर प्रवेश करना और सर्वेक्षण करना और लेना; उप-मिट्टी में खुदाई करना या खोदना ; यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना कि भूमि ऐसे उद्देश्य के लिए अनुकूलित है ; लेने के लिए प्रस्तावित भूमि की

सीमाओं और उस पर बनाने के लिए प्रस्तावित कार्य की इच्छित रेखा (यदि कोई हो) को निर्धारित करना; ऐसे स्तरों, सीमाओं और रेखा को निशान लगाकर और खाइयों को काटकर चिह्नित करना; और जहां अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता है और किसी भी खडी फसल बाड या जंगल के किसी हिस्से को काटने और साफ करने के लिए स्तरों को लिया जा सकता है और सीमाओं और रेखा को चिंहित और स्पष्ट किया जा सकता है।इसलिए , खंड 4 अधिसूचना या कार्यवाही का उद्देश्य और उद्देश्य अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता का आकलन करना है और यह अधिग्रहण का कोई अंतिम निर्णय लिए बिना प्रारंभिक जांच की प्रकृति में है ताकि यह कहा जा सके कि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

(59) बाबू बरक्या ठाकुर के मामले (ऊपर) में, बॉम्बे राज्य ने पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत 03.04.1959 दिनांकित एक अधिसूचना द्वारा

घोषणा की कि उक्त अधिसूचना से जुड़ी अ नुसूची में निर्दिष्ट भूमि की आवश्यकता का मैसर्स मुकुंद आयरन एंड स्टील लिमिटेड , भारतीय कंपनी अधिनियम , 1913 के तहत पंजीकृत एक कंपनी, अपने कारखाने के भवनों आदि के लिए। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 3 के खंड (सी) के तहत, सरकार ने उक्त अधिनियम की खंड 5-ए के तहत कलेक्टर के कार्यों को करने के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी की नियुक्ति की है। उक्त मामले में याचिकाकर्ता ने कई स्थगनों के बाद आपत्तियां दर्ज की और अपने अधिवक्ता द्वारा मौखिक प्रस्तुतियां भी दीं।उन्होंने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर से इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया कि अधिसूचना में निहित भूमि किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं थी और कार्यवाही परेशान करने वाली और दुर्भावनापूर्ण थी।यह भी कहा गया था कि तीसरे प्रतिवादी ने अधिसूचित क्षेत्र की खरीद के लिए एक निजी संधि द्वारा बातचीत की थी।उक्त मामले में याचिकाकर्ता ने अधिग्रहण के लिए अधिसूचित क्षेत्र में शामिल भूमि के कई टुकड़ों के मालिकों के साक्ष्य का नेतृत्व करने का भी प्रस्ताव किया था ताकि यह साबित किया जा सके कि अधिसूचना की अनुसूची में शामिल भूमि किसी भी सार्व जनिक उद्देश्य के लिए तीसरे प्रतिवादी द्वारा वास्तव में आवश्यक नहीं थी और तीसरे प्रतिवादी ने निजी संधि द्वारा उक्त भूमि की खरीद के लिए बातचीत भी की थी।हालाँकि , भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह के साक्ष्य पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।उक्त मामले में याचिकाकर्ता ने भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की संवैधानिकता पर हमला करने वाले कानून के कई सवाल उठाए और राज्य सरकार से खंड 39 के तहत उपरोक्त

अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति नहीं देने और न ही खंड 41 के तहत तीसरे प्रतिवादी के साथ कोई समझौता करने और न ही पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत अधिसूचना जारी करने का आदेश देने का अनुरोध किया , जिसमें घोषणा की गई कि विचाराधीन भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए थी , क्योंकि ऐसी घोषणा के बाद याचिकाकर्ता को यह तर्क देने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सक ता है कि भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं थी।तीसरे प्रतिवादी ने मुख्य रूप से इस मामले का विरोध करते हुए आग्रह किया कि रिट याचिका पूर्व -परिपक्व थी क्योंकि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा खंड 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई की गई थी और राज्य सरकार को अभी तक संतुष्ट नहीं होना था कि क्या अधिग्रहण पुराने 1894 अधिनियम की खंड 40 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए था और जब तक उपयुक्त सरकार की पूर्व सहमति नहीं दी गई थी , तब तक पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 से 37 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका था।भूमि अ धिग्रहण कलेक्टर ने तीसरे प्रतिवादी के मामले का समर्थन किया।

(60) उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने यह पाया कि पुराने 1894 के अधिनियम की खंड 5-ए में सुनवाई का प्रावधान है।

खंड 4 के तहत अधिसूचित किसी भी भूमि में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति की आपत्तियां, न केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, बल्कि एक कंपनी के लिए भी संदर्भित करती हैं।यह ध्यान देने योग्य था कि खंड 5-ए भविष्यवाणी करती है कि खंड 4 (1) के तहत अधिसूचना न केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि को संदर्भित कर सकती है, बल्कि एक कंपनी के लिए आवश्यक भूमि को भी संदर्भित कर सकती है।खंड 5-ए द्वारा विचार की गई जांच और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा सुनी गई आपत्तियों , यदि कोई हो, के बाद, उनके द्वारा आयोजित कार्यवाही के रिकॉर्ड और आपत्तियों पर उनकी सिफारिशों के साथ सरका र को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।इसके बाद सरकार को यह तय करना होगा कि आपत्तियां उचित थीं या नहीं और उन आपत्तियों पर उपयुक्त सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा।यदि सरकार आपत्तियों को खारिज करने का निर्णय लेती है और संतुष्ट होती है कि भूमि , कार्यवाही की विषय वस्तु, किसी सार्वजनिक उद्देश्य या कंपनी के लिए आवश्यक थी, तो उस प्रभाव के लिए एक घोषणा की जानी

चाहिए।इस तरह की घोषणा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए और इसमें भूमि का विवरण होना चाहिए जिसमें उसका अनुमानित क्षेत्र और वह उद्देश्य भी शामिल हो जिस के लिए इसकी आवश्यकता है।एक बार खंड 6 के तहत घोषणा किए जाने के बाद , यह निर्णायक सबूत होना था कि भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य या कंपनी के लिए थी।फिर विवादित भूमि में किसी भी हित के संबंध में मुआवजे के दावे की अन्य कार्यवाहियों का पालन करें ; और परस्पर विरोधी स्वामित्व आदि के दावे के रूप में आवश्यक जांच करने के बाद अवार्ड दिया जाता है।

(61) यह तर्क दिया गया कि पुराने 1894 के अधिनियम की खंड 4 (1) ने जानबूझकर "एक कंपनी के लिए" शब्दों को हटा दिया था और एक सार्वजनिक उद्देश्य पर जोर दिया था।यह कहा गया था कि उन शब्दों की खंड 4 के तहत अधिसूचना से अभाव, अर्थात् सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, कार्यवाही के लिए घातक थी।

(62) यह अभिनिर्धारित किया गया कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना का उद्देश्य आवश्यक सर्वेक्षण और स्तरों को लेने के बाद यह पता लगाने के लिए प्रा रंभिक जांच करना था, और यदि आवश्यक हो, तो उप-मिट्टी में खुदाई या बोरिंग करना कि क्या भूमि को उस उद्देश्य के लिए अनुकूलित किया गया था जिसके लिए इसे अधिग्रहित करने की मांग की गई थी।यह कहा गया था कि केवल खंड 6 के तहत ही सरकार द्वारा एक ठोस घोषणा की जानी थी कि उचित विवरण और क्षेत्र के साथ भूमि की आवश्यकता थी ताकि पहचान की जा सके जो एक सार्वजनिक उद्देश्य या एक कंपनी के लिए आवश्यक थी।खंड 4 के तहत जो केवल एक प्रस्ताव था , वह पुराने 1894 अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए एक निश्चित कार्यवाही का विषय बन जाता है। इसलिए , यह कहना सही नहीं था कि खंड 4 के तहत अधिसूचना में कोई भी दोष कार्यवाही की वैधता के लिए घातक था , विशेष रूप से जब अधिग्रहण एक कंपनी के लिए था और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना के बाद आवश्यक रूप से खंड 5-ए या खंड 40 के तहत उद्देश्य की जांच की जानी थी।

(63) उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ के उक्त निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना आवश्यक सर्वेक्षण और स्तरों को लेने के बाद यह पता लगाने की दृष्टि से प्रारंभिक जांच करने के लिए है , और यदि आवश्यक हो, तो उप-मिट्टी में खुदाई या बोरिंग करना कि क्या भूमि को उस उद्देश्य के लिए अनुकूलित किया गया था जिसके लिए इसे अधिग्रहित करने की मांग की गई थी ; इसके

अलावा, यह केवल खंड 6 के तहत सरकार द्वारा एक ठोस घोषणा की जानी थी कि उचित विवरण वाली भूमि और क्षेत्र ताकि पहचान की जा सके , सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या एक कंपनी के लिए आवश्यक था।

(64) प्रतिवादियो की ओर से उपस्थित माननीय अधिवक्ता एच. एस. आई. आई. डी. सी. के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चेतन मित्तल; श्री अमर विवेक, हरियाणा राज्य के माननीय अधिवक्ता, श्री 2 सुवीर सहगल, अधिवक्ता और श्री. पी. एस. खुराना अधिवक्ता हॉलांकि ने उक्त स्थिति का विरोध किया है और खुब चंद के मामले (ऊपर) और राजा राम जैसवाल के मामले (ऊपर) पर मजबूत भरोसा रखा है और उनके अनुसार पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 (1) के तहत एक अधिसूचना भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही 'शुरू' करती है।

(65) खुब चंद के मामले (ऊपर) में, उसमें अपीलकर्ताओं ने राजस्थान की हनुमानगढ़ तहसील के गांव संगरिया में कुछ जमीन 10.12.1958 को खरीदी। राजस्थान सरकार ने 14.02.1957 पर राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1953 ('राजस्थान अधिनियम'-संक्षेप में) की खंड 4 के तहत दिनांक 19.10.1956 को एक अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि उक्त भूमि, अन्य के साथ, शहर और बगीचे बिछाने के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक थी या इसकी आवश्यकता होने की संभावना थी।राजस्थान अधिनियम के प्रावधान कुछ हद तक पुराने 1894 अधिनियम के अनुरूप हैं। राजस्थान अधिनियम की खंड 5 (2) के तहत राजस्थान राजपत्र में दिनांकित 09-01-1958 एक और अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। राजस्थान अधिनियम की खंड 6 के तहत एक और अधिसूचना उक्त भूमि के संबंध में राजस्थान राजपत्र में 03.02.1959 को प्रकाशित की गई थी।राजस्थान सरकार ने राजस्थान अधिनियम की खंड 3 (सी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10-09-1955 की अधिसूचना के माध्यम से उपनिवेशीकरण के उप निदेशक , सूरतगढ़ डिवीजन को हनुमानगढ़ में मुख्यालय के साथ अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के तहत 'कलेक्टर' के कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया।सरकार ने 30.07.1959 को उपनिवेशीकरण के उप निदेशक , राजस्थान नहर परियोजना की नियुक्ति करने वाली पिछली अधिसूचना में संशोधन करते हुए दिनांक 04.06.1959 को एक और अधिसूचना प्रका शित की जिसका मुख्यालय बीकानेर में है , गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के भीतर उक्त कार्यों को पूरा करती है।उपनिवेशीकरण के उप निदेशक सूरतगढ़ ने उक्त अधिसूचना के बावजूद राजस्थान अधिनियम के तहत कार्यों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रखी।अपीला र्थियों द्वारा जांच के साथ आगे

बढ़ने के लिए उक्त उप निदेशक के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए आपत्तियां दायर की गईं और उसके बाद उन्होंने कार्यवाही में भाग नहीं लिया। हालांकि, उप निदेशक ने 11.12.1959 को एक निर्णय पारित किया जिसमें भूमि के मूल्य का आकलन 614 रूपये प्रति बीघा किया गया था।इसके बाद, उक्त उप निदेशक ने एक और निर्णय दिया और मुआवजे की दर 614 रूपये प्रति बीघा के बजाय 442 रूपये निर्धारित की।अपीलकर्ताओं ने कार्यवाही की वैधता को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

(66) उक्त पृष्ठभूमि में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सरकार को अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति प्रदान करने वाली प्रतिमा के प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।खंड 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलेक्टर उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना के सार के बारे में सार्वजनिक सूचना देगा।प्रावधान शर्तों में अनिवार्य था।हालाँकि , कुछ परिस्थितियों में , यह निस्संदेह था कि करेगा। अभिव्यक्ति का अर्थ हो सकता है के रूप में किया जाता है।राजस्थान अधिनियम की खंड 4 में उक्त निर्देश का अंतर्निहित उद्देश्य स्पष्ट था।धारा 4 की खंड (2) के तहत ऐसा नाटिस दिए जाने के बाद, उस ओर से सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी भूमि में प्रवेश कर सकता है और उसके तहत निर्धारित तरीके से मालिक के कब्जे में हस्तक्षेप कर सकता है।यह कहा गया था कि कानून ने सोचा था कि यह आत्यन्तिक रूप आवश्यक था कि ऐसे अधिकारी के दूसरे की भूमि में प्रवेश करने से पहले , उसके मालिक को इच्छित प्रवेश की स्पष्ट सूचना होनी चाहिए।इसे प्रवेश की शक्ति के प्रयोग के लिए एक आवश्यक शर्त माना गया था।उक्त शर्त का पालन न करने से अधिकारी या उसके कर्मचारियों का प्रवेश गैरकानूनी हो जाता है।उप -खंड (2) की स्पष्ट शर्तों पर, अधिकारी या उसके कर्मचारी अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में केवल तभी प्रवेश कर सकते थे जब उस शर्त का पालन किया गया हो।यदि इस का पालन नहीं किया गया था, तो वह या उसके सेवक खंड 4 (2) के तहत प्रवेश की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे , जिसके परिणामस्वरूप यदि करेगा अभिव्यक्ति को हो सकतरा है के रूप में समझा जाता है तो उप -खंड का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।इसलिए , वैधानिक इरादा स्पष्ट था कि सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य था।यदि ऐसा है, तो उक्त अनिवार्य निर्देश का पालन किए बिना खंड 4 के तहत जारी की गई अधिसूचना अमान्य होगी और उसके अनुसार की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही भी उतनी ही अमान्य होगी।

(67) बाबू बरक्या ठाकुर बनाम बॉम्बे राज्य (ऊपर) के निर्णय पर भरोसा रखा गया था।यह कहा गया था कि खंड 4 के तहत उसमें अधिसूचना में विशेष रूप से यह नहीं कहा गया था कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक उद्देश्य के लिए थी , लेकिन इसमें उस उद्देश्य के संबंध में आ वश्यक विवरण दिए गए थे जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी।उक्त मामले में यह देखा गया कि नोटिस को अमान्य करने के लिए एक औपचारिक दोष पर भरोसा करने की मांग की गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।हालाँकि, यह इस स्थिति के लिए एक प्राधिकरण नहीं हो सकता है कि यदि खंड 4 द्वारा निर्धारित अधिसूचना की सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई थी , तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता है।वह खंड को फिर से लिखना होगा।

(68) इसलिए, खुब चंद का मामला अधिग्रहण कार्यवाही की 'शुरुआत' के सवाल से संबंधित नहीं था और उक्त मामले की परिस्थितियों में खंड 4 के तहत अधिसूचना के वैध या अमान्य होने के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था।खुब चंद के मामले में निर्णय का पालन राजा राम जैसवाल के मामले (ऊपर) में किया गया था; हालाँकि, वह भी कार्यवाही की 'शुरुआत' के अर्थ में सख्ती से नहीं था, हालाँकि यह कहा गया था कि खंड 4 (1) के तहत एक अधिसूचना के रूप में भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है।भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने की अवधारणा कोई मुद्दा नहीं था जैसा कि प्रतिवादिओं की ओर से पेश माननीय वकील द्वारा तर्क दिया जाना चाहि ए।राजा राम जयस्वाल के मामले (ऊपर) में कहा गया था कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 (1) के दूसरे भाग द्वारा आवश्यक रूप से इलाके में नोटिस का प्रकाशन अनिवार्य है और जब तक कि वह अधिसूचना उसमें निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं दी जाती है, तब तक पूरी अधिग्रहण कार्यवाही दूषित हो जाएगी।न्यायालय ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करेगा क्योंकि खंड 4 (1) के तहत एक अधिसूचना भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यवाही 'शुरू' करती है और 'क्या' अभिव्यक्ति का उपयोग करती है , विधायिका का आदेश स्पष्ट हो जाता है और इसलिए, उसमें खामियों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि न्यायालय केवल एक प्रस्ताव के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उक्त मामले में जो टिप्पणियां की गई थीं, वे उक्त में शामिल मुद्दों के संदर्भ में थी जिनमें अन्य बातों के साथ साथ इस बारे थी कि क्या पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना अमान्य होगी क्योंकि यह भूमि

अधिग्रहण (कंपनी) नियम, 1963 के नियम 4 के प्रावधानों का पहले पालन किए बिना जारी नहीं की गई थी और भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अमान्य थी क्योंकि दिनांकित 13-03-1975 को अधिसूचना न तो प्रकाशित की गई थी और न ही इलाके अन्य बातों के साथ साथ इसके सार को अधिसूचित किया गया था और न ही याचिकाकर्ता को इसकी कोई सूचना दी गई थी।

(69) वास्तव में नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के लागू होने के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की 'शुरुआत' की अवधारणा केवल पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत नोटिस जारी करने जैसे किसी प्रकार के मंत्रिस्तरीय अधिनियम पर विचार करने के लिए नहीं है। वास्तव में इसके बाद इस बात को ध्यान में रखते हुए उचित विचार करने की आवश्यकता होगी कि क्या विचाराधीन भूमि, जो पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के चरण में केवल एक प्रस्ताव था, अधिग्रहण के लिए वास्तव में आवश्यक थी , इसके अलावा यह भी कि क्या यह उपयुक्त थी।यह चरण आम तौर पर तब आता है जब पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के संदर्भ में घोषणा जारी की जाती है जो पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत दायर आपत्तियों पर उचित विचार करने के बाद होती है और दिमाग के अनुप्रयोग द्वारा तय की जाती है।वास्तव में यह वह जगह है जहाँ विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत किसी मुद्दे पर दिमाग लगाया जाता है, जिसे प्रक्रिया शुरू कहा जा सकता है।

(70) सिराज अहमद सिद्दीकी बनाम प्रेम नाथ कपूर में,

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने , किराए और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 ('1972 अधिनियम'-संक्षेप में) के तहत एक किरायेदार द्वारा किराए अवशिष्ट जमा करने से संबंधित मामले पर विचार किया ताकि उसे पहली सुनवाई की तारीख को बेदखली के लिए उसके दायित्व से मुक्त किया जा सके।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता के तहत किसी मुकदमे की पहली सुनवाई की तारीख को आम तौर पर उस तारीख के रूप में समझा जाता है जिस पर न्यायालय मुकदमे में पक्षो की दलीलों और उनके द्वारा दायर दस्तावेजों में वाद में अपने दिमा ग को लागू करने का प्रस्ताव करता है ताकि मुकदमे में तय किए जाने वाले मुद्दों को तैयार किया जा सके। 1972 अधिनियम की खंड 20 (4) के प्रयोजनों के लिए 'पहली सुनवाई' अभिव्यक्ति की परिभाषा का अर्थ कुछ अलग नहीं है।परिभाषा में निर्दिष्ट सम्मन देना में उल्लिखित कदमों या कार्यवाहियों को न्यायालय द्वारा उठाए जाने वाले कदम या कार्यवाही के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि यह आखिरकार एक सुनवाई है जो परिभाषा का विषय है।सुनवाई की पहली तारीख न तो लिखित बयान दाखिल करने

के लिए निर्धारित तारीख है और न ही वह तारीख जब निचली अदालत ने किरायेदार के आवेदन पर लिखित बयान दायर करने और किराए की अवशिष्ट राशि की पूरी राशि जमा करने की अनुमति देने के लिए आदेश पारित किया था। सुनवाई की पहली तारीख को मुद्दों को तैयार करने की तारीख के रूप में लिया गया था जब न्यायालय मामले पर अपना दिमाग लगाता है।

(71) इसी तरह का प्रभाव सुदर्शन देवी बनाम सुशीला देवी का मामला है , जिसमें कहा गया था कि मुकदमे की पहली सुनवाई की तारीख लिखित ब्यान दाखिल करने के लिए निर्धारित तारीख नहीं होगी, बल्कि सुनवाई के लिए प्रस्तावित तारीख होगी , जो न्यायालय के दिमाग को विवाद में बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित तारीख है और यदि आवश्यक हो तो मुद्दों को तैयार करने के लिए लागू करना।सुनवाई की पहली तारीख को जमा किए जाने वाले किराए अवशिष्ट का मतलब होगा कि जिस तारीख को अदालत अपना निर्णय लागू करता है, जो आम तौर पर तब होता है जब वह मुद्दा तैयार करती है।

(72) राकेश वधावन बनाम जगदम्बा औद्योगिक कॉरपोरेशन में उच्चतम न्यायालय ने पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम , 1949 ('1949 किराया अधिनियम'-संक्षेप में) की खंड 13 (2) (i) के प्रावधानों पर विचार किया, जिसमें एक ऐसे मकान मालिक की आवश्यकता होती है जो अपने किरायेदार को बेदखल करना चाहता है , वह नियंत्रक को उस ओर से एक निर्देश के लिए आवेदन करे और यदि नियंत्रक किरायेदार को आवेदक के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर देने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि किरायेदार ने अपने मकान मालिक के साथ किरायेदारी के समझौते में निर्धारित समय की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर या अगले महीने की अंतिम तिथि तक ऐसा कोई समझौता की अनुपस्थिति में जिसके लिए किराया देय है, [भवन या किराए की भूमि के संबंध में उसके द्वारा देय किराए का भुगतान या निविदा नहीं दी है, तो नियंत्रक कर सकता है।] परंतुक के संदर्भ में , यदि किरायेदार 'निष्कासन के लिए आवेदन की पहली सुनवाई पर' (जोर जोड़ा गया) उचित सेवा के बाद नियंत्रक द्वारा मूल्यांकन किए गए आवेदन की लागत के साथ ऐसे बकाया पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष किराए और ब्याज अवशिष्ट का भुगतान करता है या निविदा करता है, तो किरायेदार को उपरोक्त समय के भीतर किराए का विधिवत भुगतान या बोली लगाने वाला माना जाएगा।

(73) यह देखा गया कि चंद पाल बनाम शांति अग्रवाल मामले में उच्चतम न्यायालय के विचार के लिए "पहली सुनवाई की तारीख" शब्द आया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि "पहली सुनवाई की तारीख" वह तारीख है जिस पर न्यायालय तथ्यों और मामले में शामिल विवादों पर

अपना ध्यान केंद्रित करता है।ऐसी तारीख से पहले की कोई भी तारीख सुनवाई की तारीख नहीं होगी।उदाहरण के लिए , मुद्दा तैयार करने की तारीख पहली सुनवाई की तारीख होगी जब न्यायालय को मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाना होगा।

(74) आपराधिक कानून में भी, वह तारीख जब न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए कहा जाता है, वह तारीख होती है जब न्यायालय मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाता है , जो आम तौर पर तब होता है जब आरोप तैयार किया जाता है।

(75) नारायणदास भगवानदास माधवदास बनाम राज्य पश्चिम बंगाल में

23 (2002) 5 एस. सी. सी. 440 [24 (2002) 3 एस. सी. सी. 49]

521

और अन्य (S.S.Saron, J.)

यह कहा गया था कि अपराध का संज्ञान कब लिया जाता है , यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और यह परिभाषित करने का प्रयास करना असंभव होगा कि संज्ञान लेने का क्या अर्थ है।जाँच के उद्देश्य से या उस उद्देश्य के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने को अपने आप में ऐसे कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसके द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है।जब कोई मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 200 और अध्याय XVI की बाद की खंडओं के तहत या उक्त संहिता के अध्याय XVII की खंड 204 के तहत कार्यवाही के उद्देश्य के लिए अपना दिमाग लगाता है , तभी यह सकारात्मक रूप से कहा जा सकता है कि उसने अपना दिमाग लगाया था और इसलिए, संज्ञान लिया था।

(76) महादेव गोबिंद घरगे और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, ऊपरी कृष्णा परियोजना, जामखंडी, कर्नाटक यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील की सुनवाई की तारीख वह तारीख है जिस पर न्यायालय मामले के गुण -दोष पर अपना विचार लागू करता है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "न्यायालय द्वारा सुनवाई" की अवधारणा, वास्तव में, दिवानी और आपराधिक न्यायशास्त्र दोनों के त हत सामान्य अनुप्रयोग है।किसी आपराधिक मामले में भी न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई तभी शुरू की जाती है जब वह आरो प आदि तय करने के लिए अपना दिमाग लगाता है। इसी तरह , दिवानी कानून के तहत भी यह केवल तभी होता है जब न्यायालय वास्तव में पक्ष /पक्षों द्वारा किए गए कथ नों पर अपना दिमाग

लगाता है, तो इसे मामले की सुनवाई माना जा सकता है।सुनवाई की तारीख को "कार्यवाही में कदम" अभिव्यक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।ये प्रक्रियात्मक कानून की दो अलग-अलग अवधारणाएँ थीं और इनका अलग -अलग अर्थ और अनुप्रयोग है।जो "कार्यवाही में एक कदम" हो सकता है , अनिवार्य रूप से , उसका अर्थ न्यायालय द्वारा "सुनवाई" नहीं हो सकता है।इस प्रकार कहा गया था कि "सुनवाई" के आवश्यक तत्व न्यायालय द्वारा दिमाग का उपयोग है और पक्षकार द्वारा मुकदमे को संबोधित किया गया है।

(77) इन परिस्थितियों में, पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना के अनुसरण में कार्यवाही केवल अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सर्वेक्षण और उपयुक्तता को पूरा करने के लिए प्रारंभिक जांच के लिए है।इसके अलावा , भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण करने के लिए उपयुक्त सरकार के इरादे से भी अवगत कराना ताकि वे आपत्तियां , यदि कोई हों, दायर कर सकें और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के संदर्भ में आपत्तियों को भी सुन सकें। उक्त स्तर पर दिमाग कोई अनुप्रयोग नहीं है।दिमाग का अनुप्रयोग एक ऐसे चरण में आता है जब पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा पर विचार करने के बाद आपत्तियाँ और पक्षों को सुनना जारी किया जाता है

[25 AIR 1959 एससी 1118

26 (2011) 6 एससीसी 321]

इसलिए, सुनवाई की पहली तारीख के उस तारीख होने के सिद्धांत पर जब इसमें शामिल मुद्दे पर विचार किया जाता है, यह कहा जा सकता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही उक्त तारीख को शुरू की जाती है और पहले की कार्यवाही केवल या केवल कार्यवाही में कदम थे।

(78) नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) में विधायिका ने पुराने 1894 अधिनियम के तहत कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रावधान किया है। यह प्रावधान किया गया है कि नए 2013 अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद , किसी भी मामले में पुराने 1894 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही 'शुरू' की गई थी , जहां पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत कोई निर्णय नहीं दिया गया था , तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित नए 2013 अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।मुआवजे के भुगतान के उद्देश्य से नए 2013 अधिनियम के नए प्रावधानों की प्रयोज्यता केवल तभी होगी जब पुराने

1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही 01.01.2014 से पहले 'शुरू' की गई थी, जो नए 2013 अधिनियम के प्रवर्तन के लिए निर्धारित दिन है।

(79) प्रतिवादीओ के लिए माननीय वकील ने भी इस पर भरोसा किया है

सखरबाई हरिभाउ शेल्के बनाम उप-मंडल अधिकारी बॉम्बे का मामला उक्त मामले में, यह देखा गया कि मामला नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित था। उक्त मामले में याचिकाकर्ता की भूमि को 'धर्मशाला' के निर्माण के लिए शिरडी संस्थान के लिए अधिग्रहण करने की मांग की गई थी।पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना समाचार पत्र में 27.09.2000 को प्रकाशित की गई थी।याचिकाकर्ता ने पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के संदर्भ में उक्त अधिग्रहण पर आपत्ति जताई, जिन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।इसके बाद पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा 21.09.2001 को प्रकाशित की गई।उक्त मामले में याचिका 29.04.2002 को स्वीकार की गई थी और पक्षों को अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।याचिका की सुनवाई के समय विभिन्न प्रश्न उठाए गए थे जिनमें यह भी शामिल था कि नया 2013 अधिनियम 01.01.2014 से लागू हुआ था और नए 2013 अधिनियम की खंड 114 का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उक्त अधिनियम में कोई बचत खंड नहीं था। केवल निरसन का प्रावधान था और पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही को बचाया नहीं गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि जब ऐसा कोई बचत खंड नहीं था, तो पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्य वाही आगे जारी नहीं रह सकती है। इसी उद्देश्य के लिए नया 2013 अधिनियम के तहत नई कार्यवाही शुरू करनी होगी

27 2014 (6) एयर बॉम्बे 257

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि चूंकि पुराने 1894 अधिनियम के तहत निर्णय पारित नहीं किया गया था, इसलिए पुराने 1894 अधिनियम के त हत पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। नए 2013 अधिनियम की खंड 24 प्रतिवादीओ की सहायता के लिए नहीं आएगी और इसके विपरीत पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही को निरस्त कर देगी। जिस प्रश्न पर विचार किया गया वह यह था कि नए 2013 अधिनियम का क्या प्रभाव होगा , जिसके अधिग्रहण के लिए पुराने 1894 अधिनियम के तहत पुराने 1894 अधिनियम की खंड 9 के तहत अधिसूचना तक

शुरुआत की गई थी और अदालत के निषेधात्मक आदेशों के कारण आगे की कार्यवाही नहीं की जा रही थी।यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह मामला नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। यह देखा गया कि उक्त मामले में पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत निर्णय पारित नहीं किया गया था।ऐसे मामले में , नए 2013 अधिनियम के प्रावधान मुआवजे के निर्धारण की सीमा तक लागू होंगे।खंड 9 के तहत नोटिस के चरण तक पुराने 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई और जारी रखी गई कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) ने किसी भी अस्पष्टता के लिए जगह नहीं छोड़ी और उक्त प्रावधान को सख्ती से समझना होगा।

(80) उक्त मामले में, यह प्रश्न कि पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही कब शु रू की गई मानी जाएगी मुद्दा नही था ।वास्तव में उक्त मामले में पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा 21.09.2001 को प्रकाशित की गई थी, जो कि 01.01.2014 को नए 2013 अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले थी।अतः उक्त मामले में निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

(81) प्रतिवादीओ की ओर से उपस्थित माननीय अधिवक्ता द्वारा संदर्भित दूसरा मामला राजाराम और अन्य बनाम एम. पी. राज्य (उपरोक्त) है।उक्त मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक माननीय एकल न्यायाधीश ने उस मामले पर विचार किया जहां पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 23.08.2013 की वैधता, वैधता और औचित्य पर सवाल उठाया गया था।याचिकाकर्ताओं ने इसमें यह भी प्रार्थना की कि प्रतिवादी ओ को उस भूमि पर अतिक्रमण करने से रोका जाए जिस पर वे पानी का तालाब बनाने का इरादा रखते हैं।राज्य सरकार ने धन के वितरण के लिए मंजूरी के लिए दिनांक 12.03.2013 का एक प्रशासनिक आदेश जारी किया था।बोडोरा गाँव में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कुल कृषि भूमि 243.90 हेक्टेयर थी, जिसमें से पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत विवादित अधिसूचना द्वारा, प्रतिवादी ने 194.300 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा किया था। 'जन सुनवई' दिनांक 18.06.2013 में आपत्तियों के माध्यम से उनके गांव की भूमि में एक टैंक के प्रस्तावित निर्माण के बारे में आपत्ति थी।

याचिकाकर्ताओं को वास्तव में इस तरह के निर्माण के बारे में तब पता चला जब जे. सी. बी. मशीन से लैस राज्य सरकार के अधिकारी उनकी मूल्यवान भूमि खोदने आए।उक्त स्तर पर उनके पास उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने याचिका दायर की।याचिकाकर्ताओं की ओर

से यह प्रस्तुत किया गया था कि 01.01.2014 से नए 2013 अधिनियम के प्रारंभ के सा थ, पुराने 1894 अधिनियम के अनुसार शुरू की गई पिछली कार्यवाही को बचाया नहीं गया था और समाप्त हो गई थी।यह प्रस्तुत किया गया था कि पुराने 1894 अधिनियम के तहत खंड 4 अधिसूचना नए 2013 अधिनियम के प्रारंभ से पहले जारी की गई थी। नए 2013 अधिनियम की खंड 114 के अनुसार और 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के अनुसार, निरस्त अधिनियम के तहत खंड 4 अधिसूचना और बाद की कार्यवाही नहीं बची।यह तर्क दिया गया कि नए 2013 अधिनियम के लिए आवश्यक है कि अधिग्रहण नए 2013 अधिनियम की शुरुआत के बाद से शुरू किया जाए।

(82) यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1897 के जी. सी. अधिनियम की खंड 6 (बी) पुरानी 1894 के अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी पूर्व अधिसूचना को बचाने के लिए पर्याप्त थी। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उसमें निर्दिष्ट निर्णयों और नए 2013 अधिनियम की खंड 114 में प्रयुक्त भाषा के आलोक में , पुराने 1894 अधिनियम की लंबित कार्यवाही को बचा लिया गया था और इसे नए 2013 अधिनियम के प्रारंभ पर व्यपगत नहीं माना जा सकता था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) लागू होगी और उक्त प्रावधान को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब खंड 11 के तहत कोई निर्णय नहीं दिया गया था तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित नए 2013 अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।यह प्रश्न कि कार्यवाही कब शुरू की गई थी , उक्त मामले में विचार नहीं किया गया था ; इसलिए, यह वर्तमान मामले में शामिल मुद्दों पर लागू नहीं होगा।

(83) थाइसेन स्टालुनियन जी. एम. बी. एच. बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 28, पुराने मध्यस्थता अधिनियम , 1940 ('पुराना मध्यस्थता अधिनियम '-संक्षेप में) के तहत दिए गए एक निर्णय के प्रवर्तन की , हालांकि नए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 ('नया मध्यस्थता अधिनियम'-संक्षेप में) के लागू होने के बाद, जिसने पुराने मध्यस्थता अधिनियम को निरस्त कर दिया था, पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत आयोजित कार्यवाही की कसौटी पर जांच की गई थी। मध्यस्थता कार्यवाही के पक्षकारों के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हो गए थे जो 14.09.1995 को पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत शुरू किए गए थे। 15.09.1995 को एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया था और 13.05.1996 को संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया था।एकमात्र मध्यस्थ, जिसे नियुक्त किया गया था, के समक्ष सुनवाई 07.01.1997 से 28.01.1997 तक हुई।यह निर्णय 24.09.1997 को दिया गया था।

28 ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3923

इस समय तक, नया मध्यस्थता अधिनियम 25.01.1996 को लागू हो गया था।थिसेन ने निर्णय को न्यायालय का नियम बनाने के लिए पुराने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 14 और 17 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।जबकि ये कार्यवाही उच्च न्यायालय में लंबित थी, थिसेन ने 12.02.1998 की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया।अगली तारीख को, कंपनी ने नए मध्यस्थता अधिनियम के तहत पुरस्कार के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया। यह आधार लिया गया कि मध्यस्थता कार्यवाही को 24.09.1997 पर निर्णय देने के साथ समाप्त कर दिया गया था और इसलिए, नया मध्यस्थता अधिनियम निर्णय के प्रवर्तन के लिए लागू था।प्रतिवादी -स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने निष्पादन आवेदन की रखरखाव क्षमता का विरोध किया।इसने पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत विभिन्न आधारों पर निर्णय पर आपत्तियां भी दायर की।

(84) उस मामले में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या पुरस्कार इसके प्रवर्तन के लिए नए मध्यस्थता अधिनियम द्वारा शासित होगा या क्या पुराने मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि कार्यवाही पुराने मध्यस्थता अधिनियम द्वारा नियंत्रित की जाएगी। इसके खिलाफ नाराज थिसेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।उच्चतम न्यायालय ने नए मध्यस्थता अधिनियम की खंड 85 के प्रावधानों के विशेष संदर्भ में मामले के कानून पर विचार किया , जिसमें निरसन और बचत का प्रावधान था।इसकी उप-धारा (1) में पुराने मध्यस्थता अधिनियम सहित तीन अधिनियमों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। धारा 85 की खंड (2) (ए) में परिकल्पना की गई है कि इस तरह के निरसन के बावजूद , उक्त अधिनियमों के प्रावधान, अर्थात निरसन अधिनियम नए मध्यस्थता अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में तब तक लागू होंगे जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो , लेकिन नया मध्यस्थता अधिनियम मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में लागू होगा जो नए मध्यस्थता अधिनियम के लागू होने पर या उसके बाद शुरू हुई थी।यह अभिनिर्धा रित किया गया कि उक्त बचत खंड पुराने मध्यस्थता अधिनियम को पूर्ण रूप से मिटाने से छूट देता है , जहां तक लंबित मध्यस्थता कार्यवाही का संबंध है , जिसमें निर्णय के प्रवर्तन तक पूरे पुराने मध्यस्थता अधिनियम को बचाना शामिल होगा।उक्त खंड 85 (2) (ए) ने पुराने मध्य स्थता अधिनियम के तहत अर्जित

अधिकार को प्रभावित होने से रोक दिया।यह कहा गया कि बचत प्रावधानों ने पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत अर्जित मौजूदा अधिकारों को संरक्षित किया। यह भी माना गया कि यह धारणा है कि विधायिका निहित अधिकारों को सीमित करने या छीनने का इरादा नहीं रखती है जब तक कि भाषा स्पष्ट रूप से इसके विपरीत इंगित नहीं करती है।नया मध्यस्थता अधिनियम एक उपचारात्मक क़ानून था और इसलिए , खंड 85 (2) (ए) में एक सख्त निर्माण का आह्वान किया गया था , क्योंकि यह एक निरसन प्रावधान था।लेकिन फिर यह आगे कहा गया कि जैसा कि ऊपर बताया गया है जहाँ एक व्याख्या एक अन्यायपूर्ण या असुविधाजनक परिणाम उत्पन्न करेगी और अन्य के उन प्रभावों को नहीं होगा , फिर बाद वाले के पक्ष में एक धारणा भी है।इसलिए , यह कहा गया था कि निर्णय के प्रवर्तन की जांच पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत आयोजित कार्यवाही के आधार पर की जानी चाहिए।

(85) विदेशी अवार्ड अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान दिया गया था; हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विदेशी पुरस्कार अधिनियम के तहत जब अदालत संतुष्ट हो जाती है कि विदेशी पुरस्कार उस पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत लागू करने योग्य है , तो अदालत का निर्णय दायर करने का आदेश देगी और तदनुसार निर्णय देने के लिए आगे बढ़ेगी और इस तरह से घोषित निर्णय पर एक डिक्री का पालन किया जाएगा।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि विदेशी पुरस्कार अधिनियम और विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से संबंधित नए मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों को जोड़ा जाता है तो शायद ही कोई अंतर दिखाई देगा।यह माना गया कि 24-9 पर दिया गया निर्णय -

1997 थाइसेन स्टालुनियन जी. एम. बी. एच बनाम स्टील प्राधिकरण के मामले में

ऑफ इंडिया लिमिटेड (1998 का सिविल अपील सं . 6036) जब मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के लागू होने से पहले मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हुई थी , तो इसे पुराने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा।

(86) यह प्रश्न कि क्या अधिकार अर्जित या अर्जित किया गया है , 1897 के जी . सी. अधिनियम की खंड 6 के प्रावधानों के संदर्भ में जांचा गया था और जब यह कहा जा सकता था कि पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हुई थी , तो एक पक्ष ने अधिकार प्राप्त कर लिया था कि उसके बाद दिए गए निर्णय को पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत लागू किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के

प्रावधानों के संद र्भ में प्रश्न की जांच की , और क्या यह कहा जा सकता है कि जब पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हुई थी और पक्ष ने पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत इसके बाद दिए गए निर्णय को लागू करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। विचार के लिए जो सवाल उठा वह यह था कि क्या पक्ष को कोई अधिकार प्राप्त हुआ था या यह केवल एक असंवैधानिक अधिकार था।उन मामलों का एक संदर्भ दिया गया था जो दर्शाते थे कि निहित अधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ और की आवश्यकता थी।इसे जिस अधिकार के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था , वह अस्तित्व में था, लेकिन तब यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था कि कोई कार्य किया गया था या उस अधिनियम का लाभ उठाया गया था जिसके तहत अधिकार अस्तित्व में था जब तक कि इसे निरस्त नहीं किया गया था।एक अधिनियम ने अधिकार दिया और नया मध्यस्थता अधिनियम जिसने पुराने मध्यस्थता अधिनियम को निरस्त कर दिया, अधिकार छीन लिया।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी अधिनियम के प्रावधान का लाभ उठाने के मात्र अधिकार को अर्जित अधिकार नहीं माना जा सकता है।

(87) उक्त मामला अपने स्वयं के तथ्यों और परिस्थितियों में सीमित है और यह मूल रूप से वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे को नहीं छूता है।

527

और अन्य (S.S.Saron, J.)

हालाँकि यह 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के प्रभाव को ध्यान में रखता है जब कोई अधिनियम निरस्त किया जाता है।

(88) वास्तव में जो सामने आता है वह यह है कि 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के संदर्भ में जब कोई केंद्रीय अधिनियम निरस्त किया जाता है , तो जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक निरसन खंड 6 के खंड (ए) से (ई) में उल्लिखित परिस्थितियों को प्रभावित नहीं करता है।खंड (ख) में आदेश दिया गया है कि निरसन इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम या उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी कार्य के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करता है।इसके अलावा , खंड (ग) यह आदेश देता है कि निरसन इस प्रकार निरस्त किसी अधिनियम के तहत अर्जित , उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार , विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करता है।

(89) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि पुराने 1894 अधिनियम को नए 2013 अधिनियम द्वारा 01.01.2014 से निरस्त कर दिया गया है; हालाँकि, पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ यह किसी भी तरह से पुराने 1894 अधिनियम के तहत अर्जित, अर्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करता है, जिसे निरस्त कर दिया गया था।पुराने 1894 के अधिनियम की खंड 4 के तहत केवल एक अधिसूचना जारी करने के साथ , किसी भी अधिकार , विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को अधिनियम के निरसन से पहले किसी भी पक्ष के पक्ष में अर्जित या उपार्जित या व्यय नहीं किया गया था।यह इस कारण से अधिक है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा जारी करने के साथ शुरू की गई है, जो स्वीकार किया जाता है कि 01.01.2014 से नए 2013 अधिनियम के प्रवर्तन के बाद किया गया था।इसलिए , उक्त तिथि पर, नए 2013 अधिनियम की खंड 114 (1) के प्रावधान लागू होंगे न कि इसकी खंड 114 (2) क्योंकि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

(90) प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कुछ अन्य मामले कानून का भी उल्लेख किया गया है; हालाँकि, इस सवाल पर विचार नहीं किया गया है कि पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही कब शुरू की जा सकती है।

(91) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है , पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य प्रारंभिक जांच करना और अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के संबंध में सर्वेक्षण करना है।उक्त स्तर पर मन का कोई अनुप्रयोग नहीं है।जब पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा जारी की जाती है , तो आपत्तियों पर विचार करने और पक्षों को सुनने के बाद दिमाग का उपयोग एक स्तर पर आता है।इसलिए, यह मन के अनुप्रयोग पर है कि भूमि का अधिग्रहण किया जाना है या नहीं , और इसे अधिग्रहण करने का निर्णय लिया जाता है कि यह कहा जा सकता है कि 528

उक्त तिथि पर अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी और पहले की कार्यवाही केवल या केवल कार्यवाही में कदम थे।वास्तव में विधानमंडल ने पुराने 1894 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की अभिव्यक्ति का उपयोग किया।' कार्यवाही की शुरुआत को तथ्यों और परिस्थितियों में देखा जाना चाहिए कि कार्यवाही वास्तव में कब शुरू हुई थी या कब शुरू हुई थी।दूसरे शब्दों में , मन के प्रयोग और भूमि अधिग्रहण के लिए निर्णय लेने के बाद ही चरण तक पहुंचा जा सकता है , यह कहा जा सकता है कि का र्यवाही शुरू की गई थी।यह वास्तव में वह चरण है जब पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत एक घोषणा जारी की जाती है।पूर्ववर्ती कार्यवाहियाँ कार्यवाहियों में केवल कदम हैं।

(92) मुआवजे के भुगतान जैसे उद्देश्यों के लिए , पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना की तारीख भुगतान की जाने वाली दर तय करने के उद्देश्य से ली जाती है।हालाँकि , इसका बहुत अधिक परिणाम नहीं होगा क्योंकि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में लेन-देन उस स्तर पर कम या ज्यादा रुक जाता है और बिक्री , यदि कोई हो , तो ज्यादातर परेशान बिक्री होती है ।इसलिए, पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी करने की तारीख को कार्यवाही की शुरुआत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए , बल्कि कार्यवाही में केवल एक कदम है क्योंकि कीमतें उक्त तारीख को निर्धारित की गई हैं।वर्तमान मामले में यह स्थिति नहीं होगी जहां अधिग्रहण के लिए भूमि की आवश्यकता है या नहीं और यह भी कि क्या यह अधिग्रहण के लिए उपयुक्त है , कौन सा निर्णय सर्वेक्षण द्वारा दिए गए इनपुट , भूमि मालिकों और भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर आपत्तियों के बाद ही लिया जा सकता है।यह अभ्यास विवेक के उचित प्रयोग के साथ किया जाना है, जो कार्यवाही की शुरुआत की तारीख है।

(93) इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के अनुसार 'शुरू' की गई थी क्योंकि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना नए 2013 अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले जारी की गई थी।नए 2013 अधिनियम की खंड 24 पुराने 1894 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित है जिसे कुछ मामलों में समाप्त माना जाता है।खंड 24 का उक्त शीर्षक कुछ मामलों में पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही के समापन का प्रावधान करने के लिए है।इसकी उप-खंड (1) (ए) में उल्लेख किया गया है कि नए 2013 अधिनियम में कुछ भी

निहित होने के बावजूद , पुराने 1894 अधिनियम के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के किसी भी मामले में , जहां पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत कोई निर्णय नहीं दिया गया था, तो सभी प्रावधान।

मुआवजे के निर्धारण से संबंधित नया 2013 अधिनियम लागू होना है।इसलिए , नए 2013 अधिनियम की खंड 24 की उप-खंड (1) के खंड (ए) के प्रावधानों को लागू करने के लिए पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई होगी।यह त भी होगा जब पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत कोई निर्णय नहीं दिया गया था , तो मुआवजे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए नए 2013 अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।मुआवजे के भुगतान का निर्धारण करने के उद्देश्य से पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करना नए 2013 अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए एक अनिवार्य शर्त है।नया 2013 अधिनियम लागू होने से पहले पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत केवल अधिसूचना जारी करने के साथ , यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी और इसके परिणामस्वरूप पुरस्कार पारित नहीं किया गया था, नए 2013 अधिनियम के संदर्भ में मुआवजे के निर्धारण से संबंधित प्रावधान लागू होने थे।वास्तव में , यह पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा है जिसमें प्रस्तावित अधिग्रहण को अंतिम रूप दिए जाने की दृढ़ता का एक तत्व है कि यह कहा जा सक ता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।यह कहा गया था कि खंड 4 के तहत जो केवल एक प्रस्ताव था , वह पुराने 1894 अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए एक निश्चित कार्यवाही का विषय बन जाता है। नया 2013 अधिनियम लागू होने के बाद खंड 6 के तहत जारी की गई घोषणा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नया 2013 अधिनियम लागू होने से पहले पुराने 1894 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

(94) इन परिस्थितियों में, नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे और पुराने 1894 अधिनियम के तहत की जा रही अधिग्रहण कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा।नए 2013 अधिनियम की खंड 114 के प्रावधानों में यह भी परिकल्पना की गई है कि पुराने 1894 अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था।इसका मतलब यह होगा कि इसे 01.01.2014 से नए 2013 अधिनियम के लागू होने के साथ निरस्त कर दिया गया था।नए 2013 अधिनियम की खंड 114 की उप-खंड (2) में परिकल्पना की गई है कि नए 2013 अधिनियम की खंड 114 की उप-खंड (1) द्वारा पुराने 1894 अधिनियम के निरसन को

निरस्तीकरण के प्रभाव के संबंध में 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव या प्रभाव नहीं डाला जाएगा। 1897 के जी. सी. अधिनियम की खंड 6 का खंड (सी), जो वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक है , यह परिकल्पना करता है कि जहां कोई केंद्रीय अधिनियम अब तक किए गए या इसके बाद किए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तो निरसन इस तरह से निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के तहत अर्जित , उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 की प्रयोज्यता प्रासंगिक नहीं होगी क्योंकि भूमि अधि ग्रहण की कार्यवाही है।

नया 2013 अधिनियम लागू होने से पहले केवल खंड 4 अधिसूचना जारी करने के साथ , यह माना गया है कि यह पुराने 1894 अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के बराबर नहीं होगा।

(95) उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नए 2013 अधिनियम की खंड 114, जो निरसन और बचत से संबंधित है , के लागू होने पर विचार किया जा सकता है और यह कब लागू होगा।उक्त धारा 114 की खंड (1) स्पष्ट है और यह परिकल्पना की गई है कि पुराना 1894 अधिनियम एतद्द्वारा निर स्त हो जाएगा।उप -खंड (2) में आदेश दिया गया है कि नए 2013 अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा , उप-खंड (1) के तहत निरसन को 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा। 1897 के जी. सी. अधिनियम की खंड 6 में निरसन के प्रभाव का प्रावधान है।इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 1897 का जी. सी. अधिनियम या 1897 के जी . सी. अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियम अब तक किए गए या इसके बाद किए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त कर देता है , जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो।निरसन खंड (क) से खंड (ङ) में उल्लिखित परिस्थितियों को प्रभावित नहीं करेगा।खंड (बी) में प्रावधान है कि निरसन इस तरह

से निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम या उसके तहत विधिवत किए गए या पीड़ित किसी भी कार्य के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।एक अधिनियम का निरसन आम तौर पर कानून को समाप्त करने के लिए होता है जैसे कि निरस्त कानून कभी मौजूद नहीं था।निरस्त करने का उद्देश्य 1897 के जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के तहत प्रदान किए गए कुछ उद्देश्यों को छोड़कर, अधिनियम को कानून की पुस्तकों से मिटा देना है। विधायिका का इरादा यह एकत्रित करना है कि निरसन का उद्देश्य और उद्देश्य क्या है।इस तरह के इरादे का पता बाद के विधान के स्पष्ट प्रावधानों या उसमें से आने वाले आवश्यक निहितार्थों से लगाया जा सकता है।बाद के क़ानून से यह पता लगाया जाना है कि क्या विधायिका का इरादा पहले के अधिनियम को पूरी तरह से या केवल आंशिक रूप से समाप्त करना था।

(96) गजराज सिंह बनाम एस. टी. ए. टी. 29 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब भी कोई अधिनियम निरस्त किया जाता है , तो उस पर विचार किया जाना चाहिए , सिवाय पिछले और बंद किए गए लेनदेन के , जैसे कि वह कभी अस्तित्व में नहीं था।इसका प्रभाव यह है कि अधिनियम को संसद के अभिलेख से पूरी तरह से मिटा दिया जाए जैसे कि इसे कभी पारित नहीं किया गया था; यह उन कार्यों के उद्देश्य के अलावा कभी भी अस्तित्व में नहीं था , जिन्हें शुरू किया गया था, मुकदमा चलाया गया था और निष्कर्ष निकाला गया था , जबकि यह एक मौजूदा कानून था।यह कहा गया था कि निरसन केवल रूप की बात नहीं है , बल्कि विधायिका के इरादे पर निर्भर करता है।यदि बाद की प्रतिमा में स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा इंगित किया गया इरादा पूर्व अधिनियम को निरस्त या निराकृत होना था

29 (1997) 1 एस. सी. सी. 650 दीपाक अग्रवाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

531

और अन्य (S.S.Saron, J.)

पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तो यह पूर्ण या स्वतः निरस्तीकरण का मामला होगा।

दूसरा सवाल।

(97) दूसरा प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है , वह यह है कि क्या पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत 01.01.2014 के नियत दिन से पहले जारी की गई अधिसूचना 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 के साथ पठित खंड 6 को देखते हुए चालू रहेगी।

(98) इस संबंध में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है और ऊपर विचार किया जा चुका है , नियत दिन से पहले पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना यानी 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 को देखते हुए प्रभावी नहीं रहेगी। यही कारण है कि 1897 के जी. सी. अधिनियम की खंड 6 को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए और इसे नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के संदर्भ में माना जाना चाहिए। पुराने 1894 अधिनियम के जिन प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है , वे पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही 1 के नामित दिन से पहले शुरू किए जाने की स्थिति में चालू रहेंगे , अन्यथा नहीं।इसलिए, ऐसे मामले में जहां पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत एक घोषणा प्रकाशित की जाती है और पहले अधिसूचित की जाती है , पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही को नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) (ए) को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया कहा जा सकता है और ऐसे मामले में जहां पुराने 1894 अधिनियम की खंड 11 के तहत कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित नए 2013 अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।मुआवजे का भुगतान इस परंतुक के अधीन है कि जहां अधिनिर्णय किया गया था और अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया था, तो पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी लाभार्थी नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

(99) वास्तव में, श्री एम. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री जैन , वरिष्ठ अधिवक्ता जो तर्क देना चाहते हैं, वह कुछ हद तक समान है, हालांकि एक अलग तरीके से।श्री सरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि यह केवल एक नए अधिनियम को निरस्त करने और लागू करने का मामला नहीं है, बल्कि नया अधिनियम विभिन्न लाभकारी प्रावधानों को प्रदान करता है, जिनकी पूर्ति के बिना कोई भी भूमि मालिक वंचित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसलिए , न्यायालय को लाभकारी कानून के पक्ष में झुकना चाहिए और जिनके लाभ के लिए इसे तैयार किया गया है।

(100) वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जैन , हालांकि, तर्क देते हैं कि खंड 3 (च) के साथ पठित खंड 4 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन अर्थात पुराने 532 के 'सार्वजनिक उद्देश्य' अभिव्यक्ति से संबंधित है।

1894 इसके निरस्तीकरण की तारीख से पहले के अधिनियम को नए 2013 अधिनियम की खंड 2 (1), 3 (जेड. ए.), 4 से 8 और 11 के प्रावधानों के खिलाफ लागू किया जाना चाहिए ताकि इसे जारी रखा जा सके और यह माना जा सके कि यह उन प्रावधानों के तहत बनाया या जारी किया गया है , जिन्हें 1897 के जी. सी. अधिनियम की खंड 24 को ध्यान में रखते हुए नए 2013 अधिनियम से फिर से अधिनियमित किया गया है। यदि इस तरह की कवायद की जाती है, तो यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई परिवर्धनों के माध्यम से नए 2013 अधिनियम में किए गए कई संशोधनों के कारण दोनों के बीच कई विसंगतियां होंगी।इसलिए, यह मुख्य रूप से नए कानून यानी नए 2013 अधिनियम के लाभकारी प्रावधान हैं , जिन पर अधिग्रहण की कार्यवाही को अमान्य करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए।

(101) इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2013 के नए अधिनियम में कई लाभकारी उद्देश्य और उद्देश्य शामिल हैं।नया कानून परिवर्तित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अधिग्रहण के खिलाफ कई वैधानिक उपायों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को लाता है।नया 2013 अधिनियम एक व्यापक नए समझौते के कानून के युग की शुरुआत करता है जिसका उद्देश्य प्रभावित या प्रभा वित होने की संभावना वाले लोगों के प्राचीन हितों का पुनर्वास , पुनर्वास, पर्यावरण और समाजशास्त्रीय नियंत्रण करना है , जो भूमि मालिकों और अन्य प्रभावित पक्षों के लिए अचानक विस्थापन , घर और आजीविका के नुकसान के खिलाफ जगह बनाता है।पुराने 1894 के अधिनियम की खंड 3 (च) में "सार्वजनिक प्रयोजन" अभिव्यक्ति में शामिल हैं -(i) ग्राम-स्थलों का प्रावधान, या मौजूदा ग्राम-स्थलों का विस्तार, नियोजित विकास या सुधार; (ii) नगर या ग्रामीण नियोजन के लिए भूमि का प्रावधान ; (iii) सरकार की किसी योजना या नीति के अनुसरण में सार्वजनिक धन से भूमि के नियोजित विकास के लिए भूमि का प्रावधान और बाद में योजना के अनुसार आगे का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य हरियाणा राज्य या

एकमुश्त बिक्री द्वारा उसका पूर्ण या आंशिक निपटान ; (iv) राज्य के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगम के लिए भूमि का प्रावधान ; (v) गरीब या भूमिहीन या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि का प्रावधान, या

राज्य; (vii) सरकार द्वारा प्रायोजित या उपयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विकास की किसी अन्य योजना के लिए भूमि का प्रावधान ; (viii) सार्वजनिक कार्यालय स्थापित करने के लिए किसी परिसर या भवन का प्रावधान, लेकिन इसमें कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण शामिल नहीं है।

(102) हालाँकि, नए 2013 अधिनियम की धारा 3 (ज़ा) के संदर्भ में सार्वजनिक उद्देश्य का अर्थ धारा 2 की खंड (1) के तहत निर्दिष्ट गतिविधियाँ हैं।नए 2013 अधिनियम की खंड 2 (1) में प्रावधान है कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्वास से संबंधित उक्त अधिनियम के प्रावधान तब लागू होंगे जब उपयुक्त सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उ पक्रमों और सार्वजनिक उद्देश्यों सहित अपने स्वयं के उपयोग , धारण और नियंत्रण के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है और इसमें निम्नलिखित उद्देश्य शामिल होंगे, अर्थात्:–

(क) केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित संघ की नौसेना , सैन्य, वायु सेना और सशस्त्र बलों से संबंधित रणनीतिक उद्देश्यों के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत या राज्य पुलिस की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण किसी भी कार्य के लिए, लोगों की सुरक्षा; या

(ख) अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

अर्थात्:-

(i) निजी अस्पतालों, निजी शैक्षणिक संस्थानों और नि जी होटलों को छोड़कर , आर्थिक मामलों के विभाग (अवसंरचना अनुभाग) संख्या 13/6/2009-INF, दिनांक 27 मार्च, 2012 में भारत सरकार की अधिसूचना में सूचीबद्ध सभी गतिविधियाँ या आइटम;

(ii) कृषि प्रसंस्करण, कृषि के लिए आदानों की आपूर्ति , भंडारण, शीत भंडारण सुविधाओं, कृषि के लिए विपणन बुनियादी ढांचे और संबंधित गतिविधियों जैसे कि डेयरी , मत्स्य पालन और मांस प्रसंस्करण, उपयुक्त सरकार या किसानों के सहकारी द्वारा या कानून के तहत स्थापित किसी संस्थान द्वारा स्थापित या स्वामित्व वाली परियोजनाएं।

(iii) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में निर्दिष्ट औद्योगिक गलियारों या खनन गतिविधियों , राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए परियोजना;

((iv) जल संचयन और जल संरक्षण के लिए परियोजना

संरचनाएँ, स्वच्छता;

(v) सरकार द्वारा प्रशासित परियोजना, सरकार 534

सहायता प्राप्त शैक्षिक और अनुसंधान योजनाएं या संस्थान ; (vi) खेल, स्वास्थ्य देखभाल , पर्यटन, परिवहन के लिए परियोजना

अंतरिक्ष कार्यक्रम;

((vii) कोई भी अवसंरचना सुविधा जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है और ऐसी अधिसूचना को संसद में पेश करने के बाद;

(ग) परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना;

(घ) आवास, या ऐसे आय समूहों के लिए परियोजना , जो उपयुक्त सरकार द्वारा समय -समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है;

(ई) नियोजित विकास या ग्रामीण स्थलों या शहरी क्षेत्रों में किसी भी स्थान के सुधार के लिए परियोजना या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि का प्रावधान;

(च) गरीबों या भूमिहीनों या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों , या सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य के स्वामित्व या नि यंत्रित निगम द्वारा शुरू की गई किसी भी योजना के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित या प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवासीय उद्देश्यों के लिए परियोजना।

(103) इसके अलावा, नए 2013 अधिनियम की धारा 3 (जेड) "परियोजना" को एक ऐसी परियोजना के रूप में परिभाषित करती है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है , चाहे प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो ; नए 2013 अधिनियम की धारा 3 (ओ) से संबंधित है, "बुनियादी ढांचा परियोजना" में धारा 2 की खंड (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी भी या अधिक वस्तुओं को शामिल किया जाएगा जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।नए 2013 अधिनियम के अध्याय 2 में 'सामाजिक प्रभाव और सार्वजनिक उद्देश्य के निर्धारण ' का प्रावधान है।सामाजिक प्रभाव और सार्वजनिक उद्देश्य के निर्धारण के लिए प्रारंभिक जांच की जानी है।खंड 4 'सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की तैया री' से संबंधित है ; खंड 5 'सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए सार्वजनिक सुनवाई ' से संबंधित है और खंड 6 'सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के प्रकाशन ' से संबंधित है।इसके बाद एक विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाना है।खंड 7 में 'विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के मूल्यांकन ' का प्रावधान है।हरियाणा राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए प्रस्ताव की जांच ' से संबंधित है और खंड 9 'सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से छूट ' का प्रावधान करती है जहां भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।

खंड 40 के तहत तात्कालिक प्रावधान।नए 2013 अधिनियम का अध्याय III 'खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान ' से संबंधित है।खंड 10 'खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान' से संबंधित है।ये लाभकारी प्रावधान निरस्त अधिनियम के तहत नहीं हैं।

(104) इसलिए, श्री सरीन का यह कहना सही है कि नया कानून पुराने 1894 अधिनियम का स्थान नहीं लेता है और वास्तव में यह एक नए युग को सामने लाता है और यहां तक कि श्री

जैन का यह कहना भी सही है कि नए अधिनियम और पुराने 1894 अधिनियम के बीच कई विसंगतियां हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया है और पुराने 1894 अधिनियम के प्रावधानों को 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 के प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि नए 2013 अधिनियम में नई विशे षताएँ निरस्त अधिनियम के कंकाल के लिए अपरिवर्तनीय हैं।

(105) श्री अमर विवेक द्वारा यह तर्क कि 1897 के जी. सी. अधिनियम की खंड 24 पूरी तरह से लागू नहीं है, हालांकि सही नहीं हो सकता है क्योंकि कहा गया है कि खंड 24 रद्द किए गए पुराने 1894 के अधिनियम या विनियमन के तहत की गई या जारी की गई नियुक्ति , अधिसूचना, आदेश, योजना, नियम, प्रपत्र या उप-कानून के प्रावधान पर लागू होती है, जहां तक कि यह पुनः अधिनियमित नए 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुराने 1894 के अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना जारी करना हालांकि 1897 के जी. सी. अधिनियम की खंड 24 के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी यह मुद्दा नहीं है क्योंकि इस मामले पर 1897 के जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के संदर्भ में विचार किया जाना है , जो कि निरसन के प्रभाव के संबंध में है जो नए 2013 के अधिनियम की खंड 114 (2) में ही अंकित है।इन परिस्थितियों में, यह कहा जा सकता है कि पुराने 1894 के अधिनियम को निरस्त करने के साथ 1897 के जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के संदर्भ में नए 2013 के अधिनियम में एक अलग इरादा दिखाई देता है और अन्यथा इस तरह से निरस्त किए गए अधिनियम का पिछला संचालन या उसके तहत कुछ भी किया गया या पीड़ित किया गया था; इसके अलावा, न तो कोई अधिकार , विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व प्रभावित हुआ था या न ही निरस्त पुराने 1894 के अधिनियम के तहत दायित्व अर्जित किया गया था , अर्जित किया गया था या वहन किया गया था। इसलिए , नियत दिन से पहले पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी की गई अधिसूचना 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 24 के साथ पठित खंड 6 को देखते हुए चालू नहीं रहेगी क्योंकि एक पूरी तरह से नया लाभकारी कानून प्रभावी हो गया है जिसे उन लोगों के पक्ष में पढ़ा जाना चाहिए जिनके लाभ के लिए इसका इरादा है।हालाँकि , यह एक ऐसे मामले को अपने दायरे में नहीं लेगा जहां पुराने 1894 अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही निर्धारित दिन से पहले शुरू की गई थी , जैसा कि ठीक से समझा गया था , जो कार्यवाही, जैसा कि पहले ही देखी ग ई है, अधिग्रहण के उद्देश्य से पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा जारी करने या प्रकाशित करने के साथ शुरू होगी।

तीसरा और चौथा प्रश्न।

(106) तीसरा प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है , वह यह है कि क्या सरकारी राजपत्र में पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत प्रकाशित अधिसूचना, लेकिन बाद में समाचार पत्रों में प्रकाशित, यानी नए 2013 अधिनियम के शुरू होने के बाद 01.01.2014 पर प्रकाशित अधिसूचना कानूनी रूप से टिकाऊ है ; इसके अलावा, इनमें से कौन सी प्रभावी अधिसूचना होगी जिसके आधार पर प्रकाशन की प्रक्रिया को पूरा कहा जा सकता है, अर्थात क्या अधिसूचना शुरू में राजपत्र में प्रकाशित हुई है या बाद में अधिसूचना जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है।चौथा सवाल यह है कि क्या खंड 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन इसके निरसन के बाद और नए 2013 अधिनियम के शुरू होने के बाद 01.01.2014 से अनुमत है।

(107) श्री पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिवयुग रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड बनाम मामले में पेश हो रहे हैं।हरियाणा राज्य और अन्य, 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8963 में उल्लेख किया गया है कि जहां तक उनके मामले का संबंध है , पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना राजपत्र में 27.12.2013, यानी नए 2013 अधिनियम के लागू होने से पहले प्रकाशित की गई थी।हालाँकि, समाचार पत्र में, यह 01.01.2014 पर प्रकाशित हुआ था।

(108) पुराने 1894 के अधिनियम की खंड 4 (1) में यह अपेक्षा की गई है कि जब भी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना है, तो उस आशय की एक अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए और उस इलाके में प्रसारित दो दैनिक समाचार पत्रों में , जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए और कलेक्टर को उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना देनी चाहिए।इस तरह के प्रकाशन की अंतिम तिथियां और इस तरह की सार्वजनिक सूचना देना, जिसे इसके बाद अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया जाता है।इसलिए , यह स्पष्ट है कि इस तरह के प्रकाशन की अंतिम तिथियां , यानी

अधिसूचना का प्रकाशन और ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की तारीख को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में लिया जाना चाहिए।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नए 2013 अधिनियम की खंड 11 प्रारंभिक अधिसूचना और उस पर अधिकारियों की शक्तियों के प्रकाशन से संबंधित है और उसके अवलोकन से पता चलता है कि जब भी उपयु क्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी भी क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना है, तो एक अधिसूचना, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के विवरण के साथ उस प्रभाव की प्रारं भिक अधिसूचना निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित की जानी है , अर्थात् आधिकारिक राजपत्र में। ऐसे क्षेत्र के इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनके दीपाक अग्रवाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

537

और अन्य (S.S.Saron, J.)

एक क्षेत्रीय भाषा में होगा।इसके लिए पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 में भी प्रावधान किया गया है। नए 2013 के अधिनियम में यह जोड़ा गया है कि अधिसूचना पंचायत , नगर पालिका या नगर निगम में स्थानीय भाषा में , जैसा भी मामला हो , और जिला कलेक्टर , उप-मंडल मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में प्रकाशित की जानी है।इसे उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर और प्रभावित क्षेत्रों में, निर्धारित तरीके से भी अपलोड किया जाना है।इसलिए, पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 बिल्कुल स्पष्ट है कि यह इस तरह के प्रकाशन की तारीखों में से अंतिम है और ऐसी सार्वजनिक सूचना देने को अ धिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भित किया जाना है।

(109) मैसूर राज्य बनाम अबदुल रजाक साहिब 30 में, यह था

यह अभिनिर्धारित किया कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन एक अनिवार्य आवश्यकता है।कुछ परिस्थितियों में आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन को सभी संबंधितों के लिए नोटिस माना जाता है।लेकिन पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना के मामले में , कानून ने निर्धारित किया है कि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के अलावा, कलेक्टर को संबंधित इलाके में अधिसूचना के सार का प्रचार

भी करना चाहिए।यह कहा गया था कि जब तक ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होतीं , पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 का पालन नहीं किया जा सकता था।यह आगे कहा गया कि इसके पीछे खंड 4 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।इस तरह के प्रकाशन की अनुपस्थिति में में, इच्छुक व्यक्ति अधिग्रहण कार्यवाही के बारे में अपनी आपत्तियां दर्ज करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं और वे पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत प्रदान किए गए प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित हो जाएंगे जो एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार है।

(110) वी. के. एम. कट्टा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य

हरियाणा और अन्य 31 में, यह कहा गया था कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 में यह आदेश दिया गया है कि जब भी उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए या किसी कंपनी के लिए इसकी आवश्यकता होने की संभावना है , तो उस आशय की अधिसूचना (i) आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता है; (ii) उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र, जिनमें से एक क्षेत्रीय भाषा में होगा ; और (iii) कलेक्टर की ओर से यह भी बाध्यकारी है कि वह इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना दे।उक्त मामले अन्य बातों के साथ साथ अपीलार्थी -कंपनी की ओर से , यह अन्य बातों के साथ -साथ तर्क दिया गया था कि

30 (1973) 3 एस. सी. सी 196

31 (2013) 9 एससीसी 338 538

पुराने 1894 के अधिनियम की खंड 4 (1) में उपयोग की जाने वाली भाषा , उसमें उल्लिखित प्रकाशन के सभी तीन तरीके अनिवार्य थे।यह दावा किया गया कि चूंकि अधिसूचना संबंधित इलाके में विशिष्ट स्थानों पर प्रकाशित नहीं की गई थी , इसलिए न तो अपीलकर्ता -कंपनी के पट्टेदार को और न ही अपीलकर्ता-कंपनी को इसके बारे में पता चला।यह भी कहा गया कि कोई व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया गया था।इसलिए , विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार ,

अपीलकर्ता-कंपनी को पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत आपत्तियां दर्ज करने के अपने मूल्यवान अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए , अधिसूचना के प्रकाशन का उद्देश्य दो गुना है , पहला, यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त प्रचार किया जाए ताकि भूमि मालिकों और इच्छुक व्यक्तियों को पुराने 1894 अधिनियम की खंड 5-ए के तहत अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर मिले और दूसरा , भूमि मालिकों/कब्जाधारियों को यह सूचना देना कि सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी के लिए पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 की उप-खंड (2) में उल्लिखित गतिविधियों को करने के लिए अपनी भूमि पर प्रवेश करना वैध होगा। उक्त मामले में , अधिसूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी , लेकिन पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 (1) के तहत प्रदान किए गए इलाके में अधिसूचना के सार के प्रकाशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके रुख के समर्थन में उच्च न्यायालय के साथ -साथ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी -हलफनामा या जवाब जैसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई थी।ऐसी परिस्थितियों में , न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट था कि संबंधित इलाके में पुराने 1894 अधिनियम के तहत निर्धारित अधिसूचना के सार के प्रकाशन के बारे में उक्त मामले में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विशिष्ट आधार को जानने के बावजूद, न तो राज्य और न ही भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने इसका खंडन करते हुए जवाब दाखिल करने के अवसर का लाभ उठाया।तदनुसार , यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 (1) के तहत अधिसूचना के सार का उस इलाके में कोई प्रकाशन नहीं था जिसे अनिवार्य माना जाता है।यह भी कहा गया कि यह इंगित करना प्रासंगिक था कि इलाके में इस तरह के प्रकाशन को प्रभावी बनाने से, कब्जे वाले व्यक्ति, अर्थात् मालिक या पट्टेदार के लिए खंड 5-ए के तहत जांच में अपना प्रतिनिधित्व /आपत्ति करना संभव होगा। इसके अलावा , ऐसा व्यक्ति "मालिक या कब्जाधारी" इलाके में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का हकदार है और अधिनियम के तहत प्रदान किए गए इलाके में इसका प्रकाशन न करने से, मालिक या कब्जाधारी अपना मूल्यवान अधिका र खो देता है।इन कारणों से भी , यह माना गया कि अधिग्रहण की कार्यवाही भी रद्द की जा सकती है।

(111) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित क्षेत्र के तहत एक ज़ब्ती कानून है।

इसलिए, अंतिम तिथि दीपाक अग्रवाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी अधिसूचना वह होनी चाहिए जिसमें इसे समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है।तीसरे प्रश्न का उत्तर यह होगा कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत आधिकारिक राजपत्र में, लेकिन नए 2013 अधिनियम के प्रारंभ के बाद समाचार पत्र में 01.01.2014 पर प्रकाशित अधिसूचना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं होगी क्योंकि इस तरह के प्रकाशन की अंतिम तिथियां और ऐसी सार्वजनिक सूचना देने को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के रूप में लिया जाना है।यह केवल अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन पर ही कहा जा सकता है कि प्रभावित पक्षों को नोटिस दिया गया था ताकि वे आपत्तियां दर्ज कर सकें।इसलिए , चूंकि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना 01.01.2014 पर प्रकाशित की गई थी , इसलिए इसे अमान्य माना जाएगा क्योंकि उक्त तिथि पर नया 2013 अधिनियम लागू हुआ था।इसके अलावा , चौथे प्रश्न का उत्तर यह है कि खंड 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन इसके निरसन के बाद और नए 2013 अधिनियम के शुरू होने के बाद अनुमति नहीं होगी क्योंकि खंड 6 के तहत घोषणा जारी नहीं किए जाने की स्थिति में पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही 'शुरू' नहीं की गई थी और यह घोषणा जारी होने पर ही कहा जा सकता है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया 'शुरू' की गई थी।दूसरे शब्दों में , यदि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के संदर्भ में घोषणा को पहले अधिसूचित नहीं किया जाता है , तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई नहीं कही जा सकती है और इसलिए , नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के आधार पर समाप्त हो जाएगी।

(112) उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में , यह निष्कर्ष निकाला गया है किः - (क) पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना के अनुसरण में कार्यवाही केवल अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सर्वेक्षण और उपयुक्तता को पूरा करने के लिए प्रारंभिक जांच करने के उद्देश्यों के लिए सीमित है।इसके अलावा , भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण करने के लिए उपयुक्त सरकार के इरादे से अवगत कराएं ताकि वे आपत्तियां दर्ज कर सकें और आपत्तियों को भी सुन सकें।

(ख) मुआवजे के भुगतान के उद्देश्य से, पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना की तारीख भुगतान की जाने वाली दर तय करने के उद्देश्य से ली जानी है क्योंकि एक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद भूमि की कीमतें स्थिर हो जाती हैं और आगे कोई लेनदेन नहीं होता है, इसके अलावा, यदि उक्त स्तर पर बिक्री होती है , तो ये ज्यादातर संकटग्रस्त बिक्री होती हैं।इसलिए, भले ही पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत अधिसूचना को मुआवजे की दर के निर्धारण की तारीख के रूप में लिया जाता है , लेकिन फिर भी इसे पुरा ने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने की तारीख के रूप में नहीं लिया जाना है। यह कहा जा सकता है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही उचित विवेक के प्रयोग के बाद ही शुरू की जा सकती है जो पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा का चरण है।

(ग) विधानमंडल ने नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) द्वारा पुराने 1894 अधिनियम के तहत कुछ मामलों में समाप्त मानी गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए प्रावधान किया है। यह प्रावधान किया गया है कि नए 2013 अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद किसी भी मामले में पुराने 1894 अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी, जहां इसकी खंड 11 के तहत कोई निर्णय नहीं दिया गया था , तो मुआवजे के निर्धारण से संबंधित नए 2013 अधिनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।मुआवजे के भुगतान के लिए नए 2013 अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता केवल तभी होगी जब पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही 01.01.2014 से पहले शुरू की गई थी जो नए 2013 अधिनियम के प्रवर्तन के लिए निर्धारित दिन है।

(घ) नए 2013 अधिनियम की खंड 114, जो निरसन और बचत से संबंधित है , की प्रयोज्यता इस हद तक स्पष्ट है कि इसमें यह परिकल्पना की गई है कि पुराना 1894 अधिनियम निरस्त हो जाएगा।उप-खंड (2) का प्रभाव यह है कि नए 2013 अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, उप-खंड (1) के तहत निरसन को 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभाव डालने के लिए नहीं माना जाएगा। निरसन केवल रूप का विषय नहीं है , बल्कि विधानमंडल के इरादे पर निर्भर करता है।यदि नए 2013 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से इंगित किया गया इरादा पुराने 1894 के अधिनियम को पूरी तरह या आंशिक रूप से निरस्त या निराकृत होना था , तो यह पूर्ण या स्वतः निरसन का मामला होगा।जहां तक नए 2013 अधिनियम की खंड 114 की उप-खंड (1) का प्रावधान है, पुराने 1894 अधिनियम के संबंध में निरसन कुल है; हालाँकि, उप-खंड

(2) द्वारा यह 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 के सामान्य अनुप्रयोग को प्रभावित या प्रभावित नहीं करता है।

दीपाक अग्रवाल और एन्नदर बनाम हरियाणा राज्य

541

और अन्य (S.S.Saron, J.)

(ई) नया 2013 अधिनियम अतीत के पुरातन कानून की सीमाओं को तोड़ते हुए कई समकालीन, प्रगतिशील और सामाजिक रूप से लाभकारी विधायी उपायों का प्रावधान करता है और सामाजिक प्रभाव और सार्वजनिक उद्देश्य के निर्धारण के लिए तंत्र प्रदान करता है जो पुराने 1894 अधिनियम में नहीं है। 2013 के नए अधिनियम का झुकाव उन भूमि मालिकों को कानून के लाभकारी प्रावधान प्रदान करने की ओर होना चाहिए जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है ताकि उन्हें नई विधायी व्यवस्था का लाभ मिल सके।

(च) नियत दिन से पहले पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत यानी नए 2013 अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना 1897 जी. सी. अधिनियम की खंड 6 और खंड 24 के संदर्भ में तभी प्रभावी बनी रहेगी जब पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही पहले शुरू की गई हो जो यह होगी कि पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत घोषणा के बाद उचित विचार किया गया हो। (छ) सरकारी राजपत्र में पुराने 1894 अधिनियम की खंड 4 के तहत प्रकाशित एक अधिसूचना लेकिन नए 2013 अधिनियम के शुरू होने के बाद समाचार पत्र में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की अं तिम तिथियों के रूप में कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं होगी और ऐसी सार्वजनिक सूचना देने को प्रकाशन की तारीख के रूप में लिया जाना चाहिए।अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन पर ही यह कहा जा सकता है कि प्रभावित पक्षों को नोटिस दिया गया था ताकि वे आपत्तियां दर्ज कर सकें।

(ज) खंड 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई और पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन इसके निरसन के बाद और नए 2013 अधिनियम के प्रारंभ के बाद अनुमति नहीं होगी क्योंकि खंड 6 के तहत घोषणा जारी नहीं किए जाने की स्थिति में पुराने 1894 अधिनियम के तहत कार्यवाही 'शुरू' नहीं की गई थी और यह केवल तभी कहा जा सकता है जब घोषणा जारी की जाती है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया 'शुरू' की गई थी।दूसरे शब्दों में, पुराने 1894 अधिनियम की खंड 6 के सन्दर्भ में घोषणा के मामले मे 01.01.2014 से को

पहले अधिसूचित नहीं किया गया है , भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई नहीं कही जा सकती है और इसलिए , नए 2013 अधिनियम की खंड 24 (1) के आधार पर समाप्त हो जाएगी।

(113) उपरोक्त निष्कर्षों के साथ , पूर्ण पीठ के संदर्भ का उत्तर दिया जाता है और निपटाया जाता है और मामलों को अब विचार और निपटान के लिए रोस्टर के अनुसार नियमित पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयों का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निस्पादन और उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वन्दना रानी